आज का विचार
अवसर मिलने पर आप स्वार्थी बनने की बजाय, किसी का सारथी बनने का प्रयास करें।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शनिवार, 7 मार्च, 2026 वर्ष 24, अंक 57, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बजट अनुमान और अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दी स्वीकृति

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025झ26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों, वर्ष 2026झ27 के लिए बजट अनुमानों तथा वर्ष 2024झ25 की सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों को पेश करने की मंजूरी दे दी गई है।

- मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 8 मार्च को वर्ष 2026झ27 का बजट करेंगे पेश
- मंत्रिमंडल ने सीएजी की लेखा रिपोर्टों तथा वर्ष 2024+25 के वित्तीय और विनियोजन लेखों को पेश करने को दी मंजूरी

इस संबंध में निर्णय पंजाब विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025झ26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा 8 मार्च को वर्ष 2026झ27 के लिए पंजाब के बजट अनुमानों को विधानसभा में पेश करने को भी मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्टों तथा पंजाब सरकार के वर्ष 2024झ25 के वित्तीय और विनियोजन लेखों को भी विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।

पंजाब विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल का विधानसभा पहुँचने पर किया स्वागत

पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के साथ आज पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया का पंजाब विधानसभा पहुँचने पर हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर पंजाब पुलिस द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करने के लिए पंजाब विधानसभा पहुँचे थे। स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने भी राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया को सम्मानस्वरूप स्मृति चिन्ह और पारंपरिक लोई भेंट की। राज्यपाल ने उनके हार्दिक स्वागत पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा कैबिनेट मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा, डॉ. रवजोत सिंह, संसदीय मामलों के मंत्री, पंजाब, श्री के.ए.पी. सिन्हा, मुख्य सचिव, पंजाब, बहुजन समाज पार्टी के श्री नछत्तर पाल, शिरोमणि अकाली दल के श्री मनप्रीत सिंह ईयाली और भाजपा के श्री जंगी लाल महाजन मौजूद थे।

विधानसभा द्वारा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने आज विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें बजट सत्र के दौरान सदन ने पंजाब के पूर्व मंत्री रघबीर सिंह, पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गुरदीप सिंह भैणी, स्वतंत्रता सेनानी दलीप सिंह, शहीद जोबनजीत सिंह, पनसीड के पूर्व चेयरमैन अशोक धीर, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के ससुर संदीप गिल्होत्रा, पंजाब के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणू गुप्ता, पंजाब के विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी के पिता राम कृष्ण, पंजाब के विधायक नछत्तर पाल के भाई सुखविंदर कुमार, प्रसिद्ध पत्रकार एच.के. दुआ, पूर्व सचिव पंजाब विधानसभा जी.एल. कौल, पंजाबी कवि नवराही घुगियाणवी, भारतीय टेलीविजन ब्रांड टैक्सला के संस्थापक राजा सिंह को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते समय सम्मानस्वरूप दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

केमिकल-फ्री और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देकर कृषि निर्यात बढ़ाने पर जोर : मोदी

कहा- कृषि भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

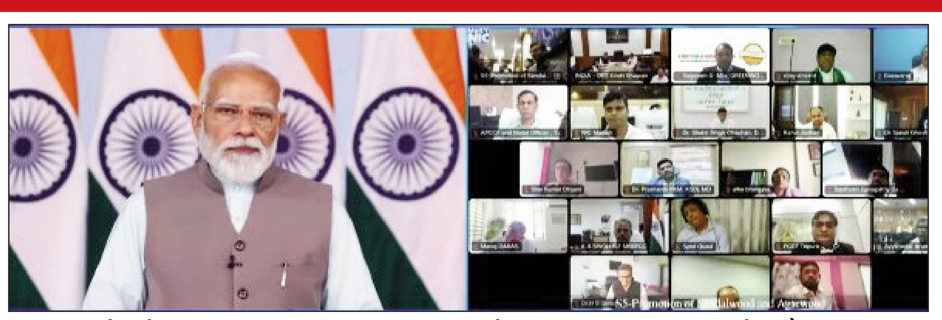

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण ऑर्गेनिक और केमिकल-फ्री खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों को निर्यात उन्मुख बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। ऐसे में भारत के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती और केमिकल-फ्री उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का एक हाईवे बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्रमाणन, प्रयोगशालाओं और आवश्यक ढांचे के विकास पर विचार कर रही है, लेकिन इस दिशा में सभी संबंधित पक्षों को मिलकर प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि केवल एक फसल पर निर्भर रहने से किसानों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और आय के विकल्प सीमित हो जाते हैं। इसी कारण सरकार फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दे रही है। खाने के तेल और दालों के लिए राष्ट्रीय मिशन तथा प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन जैसे प्रयास कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ है। इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 10 करोड़ किसानों को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है।

उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सुधार के कारण किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना तक लाभ मिल रहा है। संस्थागत ऋण की पहुंच 75 प्रतिशत से अधिक किसानों तक हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है। इन पहलों के कारण किसानों का जोखिम कम हुआ है और कृषि क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अनाज, दालों और तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, लेकिन 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा भरना आवश्यक है। इस वर्ष के बजट में इसी दिशा में कई नए अवसर प्रदान किए गए हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने और कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार तेजी से खुल रहे हैं और दुनिया की मांग में बदलाव आ रहा है। ऐसे में भारत को अपनी कृषि को निर्यात उन्मुख बनाने पर ध्यान देना होगा। देश के विविध जलवायु क्षेत्रों और समृद्ध एग्रो-क्लाइमेटिक जोन का लाभ उठाकर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

बजट में कृषि पर विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में उच्च मूल्य वाली कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को क्षेत्रीय आधार पर प्रोत्साहित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर केरल और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में नारियल का उत्पादन होता है, लेकिन कई स्थानों पर पेड़ पुराने हो चुके हैं और उनकी उत्पादकता कम हो गई है। इसलिए बजट में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों में टेम्पर्ड नट फसलों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। जैसे-जैसे निर्यात उन्मुख उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके लिए सरकार, कृषि विशेषज्ञों, उद्योग और किसानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि उच्च मूल्य वाली कृषि को सामूहिक प्रयासों से बढ़ावा दिया जाए तो भारत का कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों की खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करें: नायब सैनी

मुख्यमंत्री बोले- माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा देकर पानी की बचत करें

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी प्रदेश में मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों की खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि कम कृषि भूमि में किसान अधिक आमदनी कर सकें। उन्होंने माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा देकर पानी की बचत करने के लिए भी किसानों में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री यहां हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन हरियाणा तथा रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हरियाणा का विमोचन कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति निर्धारण पर आयोजित बैठक (विपणन सत्र 2026-27) की अध्यक्षता भी की और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल,मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक ,हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ रविंदर सिंह चौहान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हितेश कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिनल जड़ी-बूटियों के निर्यातकों में शामिल है और इस क्षेत्र में हरियाणा भी अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत कृषि ढांचे के कारण महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों को टिकाऊ और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो यह क्षेत्र किसानों और उद्यमियों के लिए बड़े आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों का क्षेत्र केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का निर्माण और मार्केटिंग जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। इस कारण यह क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा : अमित शाह

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण देश अब इस समस्या से मुक्ति के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

कटक के मुंडुली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों के समन्वित और लगातार अभियानों के कारण देश अब दशकों पुरानी इस समस्या से छुटकारा पाने की दहलीज पर खड़ा है।

उन्होंने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तय समयसीमा के भीतर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सीआईएसएफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

शाह ने कहा, चाहे ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना , नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सीआईएसएफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने तथाकथित रेड कॉरिडोर की अवधारणा पर भी प्रहार करते हुए कहा कि सुरक्षा बल उन लोगों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जो तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इससे पहले, अमित शाह भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उनका स्वागत ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल समेत अन्य नेताओं ने किया। इसके बाद वे सीआईएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंडाली रवाना हुए।

अमेरिका का रुसी तेल खरीद पर छूट से संबंधित बयान भारतीय संप्रभुता का अपमान: कांग्रेस

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

अमेरिका के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट के भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने को लेकर 30 दिन की अस्थाई छूट से जुड़े बयान को लेकर कांग्रेस ने इसे देश की संप्रभुता का अपमान बताया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत को अनुमति देने की भाषा उन देशों के लिए इस्तेमाल होती है जिन पर प्रतिबंध लगे हों, न कि भारत जैसे जिम्मेदार साझेदार के लिए। मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक स्पेस छोड़ रही है और भारत को एक 'अमेरिका के अधीन अभाषी देश' बना दिया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि भारत की विदेश नीति जनता की सामूहिक इच्छा से निकलती है और यह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। आज जो हो रहा है वह नीति नहीं बल्कि एक समझौता कर चुके व्यक्ति के शोषण का नतीजा है।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमृत काल में भारतीय प्रधानमंत्री को तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों से अनुमति मांगनी पड़ रही है, जो भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय साख के लिए बेहद अपमानजनक है। अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने के बजाय भारत को स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए और सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में खुद निर्णय लेना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा नीति के कारण अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

भेदभाव-स्वार्थ त्यागकर देश के लिए समर्पित हों, तभी भारत संपूर्ण मानवता को शांति-समृद्धि का मार्ग दिखाएगा: भागवत

एजेंसी (हि.स.)
जैसलमेर

राजस्थान के जैसलमेर में दादा गुरुदेव आचार्य श्री जिनदत्त सूरी के 871वें चादर महोत्सव के अवसर पर सामाजिक समरसता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जैन और सनातन परंपरा के संतों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों का संगम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम पूर्णतः समरसता और सामाजिक एकता के भाव पर आधारित था, जिसमें गच्छाधिपति जिनमणिप्रभ सागर के नेतृत्व में धर्म, तीर्थ एवं संस्कृति की रक्षा का संकल्प दोहराया गया।

इस अवसर पर डॉ. भागवत ने समाज से केवल उपदेशों तक सीमित न रहकर आचरण में परिवर्तन लाने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने मित्रों और परिचितों के दायरे में विभिन्न जातियों, पंथों, भाषाओं और प्रदेशों के लोगों को शामिल करें। जब हम सुख-दुख, खान-पान और सामाजिक जीवन साझा करेंगे, तभी वास्तविक सामाजिक शक्ति प्रकट होगी।

डॉ. भागवत ने भारतीय संस्कृति की चिरंतनता, विविधता में एकता और सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दादा गुरुदेव आचार्य जिन दत्त सूरी की 871 वर्ष पुरानी चादर को भारत की सनातन संस्कृति की जीवटता का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा कि यह चादर उस सत्य का प्रतीक है जिसे न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं और न ही जल भिगो सकता है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा पहचाने गए उस शाश्वत सत्य का प्रमाण है जो सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने सभी को यह संकल्प दिलाया कि यदि हम आपसी भेदभाव और स्वार्थ को त्यागकर देश के लिए समर्पित हो जाएं, तो भारत न केवल परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनेगा बल्कि एक विश्वगुरु के रूप में संपूर्ण मानवता को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। डॉ. भागवत ने जैन दर्शन के अनेकांतवाद सिद्धांत की सराहना करते हुए कहा कि सत्य इतना व्यापक है कि उस तक पहुंचने के मार्ग अलग-अलग होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि विविधता वास्तव में एकता का श्रृंगार और उत्सव है, न कि विभाजन का कारण।

अपने भाषण में उन्होंने एक रेल यात्रा की मार्मिक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि समाज में झगड़े और संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते और अपने एकत्व के भाव को भूल जाते हैं। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं, तब स्वार्थ और भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाएं युद्धों को नहीं रोक सकतीं। इसके लिए मानव के भीतर करुणा और एकात्मता का भाव होना आवश्यक है।

इस अवसर पर गच्छाधिपति जिन मणिप्रभसागर महाराज ने कहा कि समरसता ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। भारत का ध्वज पूरे विश्व में सम्मानपूर्वक लहराने के लिए सभी संप्रदायों के संतों को एकता और अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा।

उन्होंने भगवान महावीर और भगवान राम के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में जातिवाद और छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने युवाओं को सही दिशा देने और समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने का आान किया।

इस अवसर पर संघ और समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान चादर महोत्सव की स्मृति में डाक टिकट, विशेष सिक्के और दादा गुरुदेव पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, संयोजक तेजराज गुलेचा तथा पद्म भूषण डॉ. डीआर मेहता सहित अनेक समाजसेवियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

70 हजार करोड़ मिलते तो हिमाचल होता कर्ज मुक्त, ओपीएस कभी बंद नहीं होगी: सुक्खू

मुख्यमंत्री ने सभी महिला मंडलों को 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रदेश को केंद्र से उतनी वित्तीय सहायता मिलती जितनी पिछली सरकार को मिली थी, तो आज हिमाचल प्रदेश कर्ज मुक्त होता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बंद नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने छात्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की और जनसभा में उपस्थित सभी महिला मंडलों को 51-51 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता नरेश चौहान की मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।

सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल को मिलने वाला लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार को पांच वर्षों में 54 हजार करोड़ रुपये आरडीजी और 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में मिले, लेकिन वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण प्रदेश का कर्ज कम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग एक हजार करोड़ रुपये के भवन बनाए गए जो आज खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये आरडीजी मिला, लेकिन अगले वित्त वर्ष से वह भी बंद हो गया है। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस कभी बंद नहीं होगी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया शुभारंभ

मंडी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीक पर 28.44 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने यहां पर स्वयं पहली सर्जरी को देखा। इससे पूर्व, जिला शिमला के अटल सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाणा में अब तक 151 तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 92 ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए जा चुके है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली के स्तर पर हाईएंड तकनीक का समावेश किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक के बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर और बंबर ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर, प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, नरेश चौहान, लाल सिंह कौशल, जीवन ठाकुर, जगदीश रेड्डी, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंघमार, सचिव प्रियंका बासु, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस अब दरें बढ़ाने की तैयारी में : भारद्वाज

- कहा, यह कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर का बड़ा उदाहरण

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के समय 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सरकार अब बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर महंगाई का नया बोझ डालने की तैयारी कर रही है।

शिमला से शुक्रवार को जारी बयान में संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान मुफ्त बिजली और कई अन्य गारंटियों का वादा करके लोगों को आकर्षित किया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही सरकार बिजली महंगी करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर का बड़ा उदाहरण है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सामने आ रही जानकारी के अनुसार प्रदेश में बिजली की दरों में लगभग एक रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उनका कहना है कि बिजली दरों में इस संभावित बढ़ोतरी से प्रदेश की जनता पर सालाना करीब 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए नियामक आयोग के समक्ष लगभग 8593 करोड़ रुपये की मांग रखी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और प्रबंधन की कमियों का बोझ अब सीधे जनता पर डालने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने वाली बिजली को वापस लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिसका असर बिजली व्यवस्था और दरों पर पड़ सकता है। उनके अनुसार पहले यह बिजली सीधे बिजली बोर्ड को मिलती थी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी। लेकिन अब व्यवस्था बदलने के कारण बिजली बोर्ड को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदने की स्थिति बन सकती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियों और मुफ्त बिजली के वादों के जरिए लोगों को उम्मीदें दी थीं, लेकिन अब वही वादे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय सरकार ऐसे फैसलों की तैयारी कर रही है जिससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसका सड़कों से लेकर सदन तक विरोध करेगी।

खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन की आशंका के चलते कश्मीर घाटी में सख्त प्रतिबंध

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

कश्मीर घाटी में शुक्रवार को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि आज दोपहर की नमाज के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो सकते हैं। अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों में खामेनेई की मौत के विरोध में लगातार छठे दिन घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। प्रदर्शनों के बाद सोमवार को यह प्रतिबंध लगाए गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बैठक के बाद विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित स्थानों की संख्या मंगलवार को कुछ दर्जन से घटकर गुरुवार को 10 से भी कम रह गई है। सरकार ने शनिवार तक शिक्षण

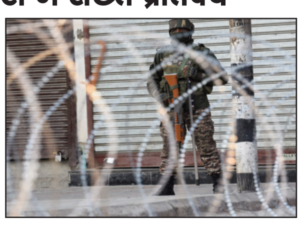

संस्थानों को बंद कर दिया है और मोबाइल इंटरनेट की गति कम कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को रोकने के लिए तड़के ही शहर भर में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। शहर में प्रवेश करने वाले महत्वपूर्ण चौराहों पर कंटीले तार और बैरिकेड लगाए गए हैं। रविवार देररात श्रीनगर के केंद्र में स्थित लाल चौक के चारों ओर बैरिकेड लगाकर क्षेत्र को सील करने के बाद शहर का प्रतिष्ठित घंटाघर अभी भी प्रतिबंधित क्षेत्र बना हुआ है। खामेनेई की हत्या के बाद रविवार को घंटाघर में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे सील करने का कदम उठाया गया।

बिलासपुर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

बिलासपुर। जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रतीक गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों का मामला वर्तमान में किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, यदि वे आपसी सहमति के आधार पर अपने विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

सड़कों पर एलईडी स्क्रीन्स, फिजूलखर्ची और सड़क सुरक्षा से खिलवाड़: शिवसेना

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर इकाई ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर लगाई जा रही विशाल एलईडी स्क्रीन बोर्डों की कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी ने इसे जनता के टैक्स के पैसे की फिजूलखर्ची और वाहन चालकों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ करार दिया है। प्रदेश केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि किसी भी 'स्मार्ट सिटी' का वास्तविक अर्थ गड्ढा मुक्त सड़कें, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था, हर घर तक स्वच्छ पेयजल, बिना कटौती के बिजली आपूर्ति, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, विश्वस्तरीय सरकारी अस्पताल और आम नागरिकों के लिए सुलभ मोहल्ला क्लीनिक जैसी बुनियादी सुविधाओं से

होना चाहिए। साहनी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन इन मूलभूत नागरिक समस्याओं के समाधान के बजाय करोड़ों रुपये खर्च कर शहर की व्यस्त सड़कों और चौराहों पर एलस्क एलईडी न लगाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यस्त चौराहों पर इस प्रकार की एलईडी स्क्रीन वाहन चालकों का ध्यान भटका सकती हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उनके अनुसार यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा मानकों और मोटर वाहन अधिनियम।1988 की भावना के भी विपरीत है। साहनी ने आरोप लगाया कि प्रशासन जनता की सुरक्षा की अनदेखी कर राजस्व कमाने को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने मांग की कि शहर में लगाई जा रही सभी एलईडी स्क्रीन का तत्काल रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर जम्मू नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।

साहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन जनता की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी करता रहा तो शिवसेना (यूबीटी) केवल प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सड़कों पर उतरकर जोरदार लोकतांत्रिक आंदोलन छेड़ेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर भरत गुप्ता , संजय भटट्, अदित्य महाजन उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

कश्मीर वहीद पारा ने मिशन युवा के तहत भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और विधायक वहीद उर रहमान पारा ने शुक्रवार को मिशन युवा के तहत भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ पदों पर भर्ती केवल दो संस्थानों के स्नातकों तक ही सीमित रखी जा रही है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पारा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आईआईएम जम्मू और आईआईटी जम्मू के उम्मीदवारों तक ही सीमित प्रतीत होती है और उन्होंने पूछा कि जम्मू-कश्मीर के अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए अवसर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय और क्षेत्र के अन्य विश्वविद्यालयों को भी भर्ती के लिए विचार किया जाना चाहिए।पारा ने कहा कि भर्ती को दो संस्थानों तक सीमित करने से जम्मू-कश्मीर के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। उन्होंने आवेदन सीमित करने के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया जबकि आईआईएम जम्मू और आईआईटी जम्मू दोनों में जम्मू-कश्मीर के बाहर के छात्रों की संख्या काफी अधिक है। पारा ने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है तो सरकार को देश भर के संस्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन खोलने पर विचार करना चाहिए। अगर वाकई योग्यता ही मायने रखती है तो देश भर के आईआईएम और आईआईटी में आवेदन खोले जाने चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके, न कि इसे सिर्फ दो संस्थानों तक सीमित रखा जाए।पीडीपी नेता ने अपने पोस्ट में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी टैग किया और मिशन युवा के तहत भर्ती प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मिशन युवा जम्मू और कश्मीर में उद्यमिता, रोजगार सृजन और युवा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की एक पहल है।

कठुआ में बायर/सेलर मीट का आयोजन बागवानी उत्पादों के बेहतर विपणन पर जोर

कठुआ। जम्मू-कश्मीर के बागवानी विभाग (प्लानिंग एंड मार्केटिंग) की ओर से शुक्रवार को 'किसानों को बाजार से जोड़ना' थीम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वूमेन कठुआ में एक बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी उत्पादों के विपणन को मजबूत करना और किसानों, व्यापारियों व खरीदारों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना था। इस अवसर पर प्रमुख बागवान, किसान उत्पादक संगठन, व्यापारी, निर्यातक और कृषि उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम ने खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे संवाद के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया, जिससे बागवानी उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कार्यक्रम के दौरान बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बातचीत और ज्ञान-विनिमय सत्र आयोजित किए गए। इनमें बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को अपनाने और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-मार्केट प्लेटफॉर्म) से जुड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विभाग ने किसानों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण, क्षमता विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम में कठुआ के अलावा सांबा, उधमपुर, रियासी और जम्मू जिलों से आए किसान, एफपीओ, व्यापारी और संस्थागत खरीदार भी शामिल हुए। इससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण और दीर्घकालिक व्यापारिक अवसरों के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बागवानी विभाग के निदेशक गुलाम जीलानी जरगर ने कहा कि सरकार बागवानों और खरीदारों के बीच मजबूत विपणन तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और जम्मू-कश्मीर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत इंटीग्रेटेड पैक हाउस, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग लाइनों की स्थापना तथा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है, जिससे फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कठुआ में आयोजित यह पहली बायरद्सेलर मीट है, जो किसानों और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। उन्होंने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए बाजार से किसानों की सीधी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सड़क सुरक्षा जागरूकता पर जीडीसी कठुआ में अंतर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता आयोजित

कठुआ। सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में शुक्रवार को अंतर-महाविद्यालय भाषण (एलोक्यूशन) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें जिले के छह कॉलेजों के कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जीडीसी महानपुर, जीडीसी बसोहली, जीडीसी हीरानगर, जीडीसी मढ़हीन, जीसीडब्ल्यू कठुआ और मेजबान जीडीसी कठुआ के छात्र-छात्राओं ने सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का मूल्यांकन सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रो. पी.के. राव और प्रो. स्वरूप चंदर (पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी) ने किया। परिणामों में जीडीसी कठुआ के राहुल ठाकुर ने प्रथम, ध्रुव देव सिंह ने द्वितीय तथा जीडीसी बसोहली के रितेश डोबलिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब डिविजनल स्तर की प्रतियोगिता में जिला कठुआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

हिमाचल के होटल निजी हाथों में देने का फैसला 'हिमाचल ऑन सेल' : जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के आठ प्रमुख होटलों को आउटसोर्सिंग के जरिए निजी ऑपरेटरों को सौंपने का प्रदेश सरकार का कदम सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की 'हिमाचल ऑन सेल' की नीति है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य के बहुमूल्य संसाधनों को निजी हाथों में सौंप रही है और जनसंपदा को अपने 'मित्रों' को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देवभूमि हिमाचल की जमीन, पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए गए हिमाचल प्रदेश भू सुधार एवं किराएदारी अधिनियम 1972 की धारा 118 में छूट देने के नाम पर सरकार

पहले ही 'हिमाचल ऑन सेल' की मुहिम चला रही है और अब पर्यटन निगम के होटल भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष पहले ही आशंका जता चुका था कि सरकार जानबूझकर राज्य के सुचारू रूप से चल रहे और लाभ देने वाले होटलों को कमजोर कर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब सामने आए पर्यटन विभाग के पत्र संख्या ओपी/ओ एंड एम/टीडीसी/26 से साफ हो गया है कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। जयराम ठाकुर के अनुसार पर्यटन विभाग की सूची में बिलासपुर का होटल लेक-व्यू, चिंडी का होटल ममलेश्वर, फागू का होटल एप्पल ब्लॉसम, रोहड़ू का होटल चांशल, कुल्लू का होटल सर्वरी, कसौली का होटल ओल्ड रॉसकॉमन, परवाणू का होटल शिवालिक और खड़ापत्थर का होटल गिरिगंगा शामिल हैं। उनका कहना है कि इन होटलों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के आधार पर निजी कंपनियों को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'व्यवस्था परिवर्तन' का नारा देने वाली सरकार अब हिमाचल को बेचने की राह पर चल पड़ी है।

जम्मू में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर हुआ विवाद

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में कुछ युवकों पर सनातन धर्म और देवी-देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है जिसके बाद लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में एक युवक यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर माता का प्रवेश हो गया है। इसी दौरान जब उसने लाल चुन्नी मांगी तो पास खड़े दूसरे युवक ने उसके सिर पर टोपी रख दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद जम्मू के कई युवाओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे सनातन धर्म तथा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया। युवाओं का कहना है कि इस तरह की हरकतें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। वहीं जम्मू के कुछ युवाओं ने प्रशासन से मांग की है ।

विद्यार्थी जीवन में मेहनत और अनुशासन अति आवश्यक: हर्षवर्धन चौहान

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

उद्योग एवं संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र के श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उद्योग मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के पूरे जीवन के लिए अत्यंत बहुमूल्य होता है। इस समय में विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तथा अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संस्कार, मेहनत और जिम्मेदारी की भावना भी सिखाती है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आ'ान किया कि वे पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में भी भाग लें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। हर्षवर्धन चौहान ने नौजवानों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया।

राष्ट्र की सेवा करना बड़े गर्व की बात: कविंदर गुप्ता

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और देश की सेवा करने की जिम्मेदारी को बड़े गर्व की बात बताया। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि कवींद्र गुप्ता को बधाई लद्दाख एक छोटा सा क्षेत्र था, और वह एक सक्षम व्यक्ति हैं। अब से, लोग उनकी क्षमताओं को भी पहचानेंगे। गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, वह संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे और समर्पण, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। गुप्ता ने लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान निरंतर मार्गदर्शन और पूर्ण समर्थन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। आठ

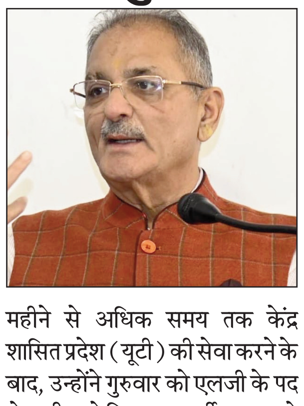

महीने से अधिक समय तक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की सेवा करने के बाद, उन्होंने गुरुवार को एलजी के पद से इस्तीफा दे दिया। 66 वर्षीय गुप्ता को 18 जुलाई, 2025 को लद्दाख एलजी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 2019 में यूटी को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर से अलग करने के बाद से वह तीसरे एलजी थे। जम्मू के एक वरिष्ठ भाजपा नेता, गुप्ता पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के उपमुख्यमंत्री और विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह जम्मू के मेयर भी रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

मौसम | आने वाले दिनों में दिख सकता है मौसम में हल्का बदलाव

हिमाचल में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती

- कल मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 9 और 10 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बन रही है। हालांकि फिलहाल किसी तरह का मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

अगले सात दिनों के पूर्वानुमान में मौसम अधिकतर शुष्क रहने के साथ-साथ बीच-बीच में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 8 मार्च को एक बार फिर मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 9 और 10 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 11 और 12 मार्च को भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की भारी बारिश या बर्फबारी की चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय है और इसकी हवाओं की गति करीब 115 नॉट्स तक दर्ज की गई है। इसके साथ ही जम्मू और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर भी ऊपरी स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी मध्य स्तर की हवाओं के साथ सक्रिय है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में हिमाचल के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस सर्दी के मौसम में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है। यही कारण है कि फरवरी और मार्च की शुरूआत में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर कमजोर रहा है। मौसम शुष्क रहने से प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है और दिन के समय हल्की गर्मी का असर महसूस होने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना जिले के नेरी में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक दर्ज न्यूनतम तापमान के आंकड़ों में शिमला में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सुंदरनगर में 11.1 डिग्री, भुंतर में 10.1 डिग्री, कल्पा में 7.5 डिग्री और धर्मशाला में 12.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा, स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल युवाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई

कड़ी मेहनत और अनुशासन से युवाओं ने पास की कठिन परीक्षा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा के घोषित परिणामों में सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी युवा अपने सपनों, कड़ी मेहनत, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

उन्होंने कहा कि वे पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से इन सभी प्रतिभाशाली युवाओं को हृदय से बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण के बल पर इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि उनके माता-पिता, परिवार, शिक्षकों और पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। श्री नायब सिंह सैनी ने विशेष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि घोषित परिणामों में हरियाणा के प्रतिभाशाली युवा एकांश ने अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने एकांश को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे हरियाणा के लिए गर्व का क्षण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा आज केवल खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पलवल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं कोई कमी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पलवल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। 200 बेड के जिला अस्पताल और 50 बेड के सब-डिविजनल अस्पताल के माध्यम से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री रघुबीर तेवतिया द्वारा पलवल और बल्लभगढ़ के बीच ट्रामा सेंटर बनाने जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्थानीय विधायक जिस स्थान की बात कर रहे हैं, उससे 500 मीटर दूरी पर 200 बेड का जिला अस्पताल, पलवल स्थित है। दूसरी तरफ केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का सब-डिविजनल अस्पताल भी स्थित है, जिससे लोगों को उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विधायक द्वारा बताई गई ट्रैफिक जाम की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पलवल में जाम की स्थिति नहीं है। पहले जाम की समस्या होती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर बनने के बाद यातायात व्यवस्था काफी सुगम हो गई है।

अंबाला छावनी के गांव शाहपुर में स्थापित होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान: अनिल विज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान पर 11.65 करोड रूपए आएगी लागत, सैकडों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगें सृजित- विज

हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी को नई सौगात मिलने जा रही है जिसके तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान अंबाला छावनी के गांव शाहपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन भी इसी गांव में स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान और आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी के गांव शाहपुर की 13 एकड 5 कनाल और 4 मरला भूमि पर ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान और आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान और आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना पर लगभग 11.65 करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान और आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सैकडों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होगें। उन्होंने बताया कि इस संस्थान के माध्यम से आसपास के जिलों के हजारों प्रशिक्षित युवाओं को ओर अधिक हुनरमंद बनाने अर्थात अधिक कौशलयुक्त तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना से प्रति सप्ताह लगभग 300 वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी।

श्री विज ने बताया कि वे चाहते हैं कि हरियाणा में परिवहन सुविधाओं को ओर अधिक सुचारू व सुगम बनाया जाए और इसके लिए उनके द्वारा नित नए दिन तकनीकी रूप से आधुनिक तरीके से सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बस टैजेंकिंग सिस्टम और बस अडडों पर बसों के आवागमन की स्थिति की जानकारी डिजीटल रूप में दशार्ने के लिए डिजीटल बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हुए है, जिस पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

सुखोई विमान दुर्घटना में शहीद हुए वीर अधिकारियों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा : आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के सुखोई र४-30टङ्क लड़ाकू विमान दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोनों जांबाज अधिकारी देश की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित थे। कर्तव्य पालन के दौरान उनका इस प्रकार असमय चले जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा।

आरती सिंह राव ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य व शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ (29 वर्ष) मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते थे, जबकि वर्तमान में उनका परिवार गुरुग्राम के सेक्टर-22बी में रह रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के ये वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा करते हुए अमर हो गए हैं और उनका बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा।

केयू न्यूज लैटर विश्वविद्यालय की सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम: डॉ. प्रीतम सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

विश्वविद्यालय राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत: प्रो. महासिंह पूनिया

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के कुशल मार्गदर्शन में जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित तथा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित केयू न्यूज लैटर के बारहवें अंक का विमोचन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉ. प्रीतम सिंह तथा जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने संयुक्त रूप से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र में किया।

इस अवसर पर डॉ. प्रीतम सिंह ने कहा कि केयू न्यूज लैटर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, अकादमिक तथा अन्य उपलब्धियों की सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने केयू न्यूज लैटर के एडिटर-इन-चीफ प्रो. महासिंह पूनिया और पूरी एडिटोरियल टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय की मासिक गतिविधियों को संकलित कर देश-प्रदेश तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि विश्वविद्यालय अपने कंटेंट को स्वयं के मीडिया माध्यमों के जरिए जनहित में प्रसारित कर रहा है।

इस अवसर पर जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि केयू न्यूज लैटर के मार्च अंक में विश्वविद्यालय से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को स्थान दिया गया है। इनमें शोधार्थियों को रिसर्च अवार्ड प्रदान करना, विश्वविद्यालय परिषद की 290वीं बैठक, कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार मिलना, चार युवा वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार प्रदान किया जाना, स्किल विकास के लिए अभ्यास व धैर्य की आवश्यकता, कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड मिलना, 2047 के विकसित भारत में युवा उद्यमियों की भूमिका, कला समीक्षा कार्यशाला, मीडिया विद्यार्थियों का विधानसभा बजट सत्र-2026 का शैक्षणिक भ्रमण, ललित कला विभाग में कला प्रदर्शनी, आईसीआईसीआई बैंक में 25 विद्यार्थियों का चयन, विभिन्न विभागों में रोस्ट्रम प्रतियोगिताएं, 37 परीक्षाओं के परिणाम तथा विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं।

प्रो. महासिंह पूनिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में केयू न्यूज लैटर एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर केयू न्यूज लैटर की एडिटोरियल टीम के सदस्य डॉ. अभिनव, अमित जागड़ा, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. सतीश राणा, राजेश शर्मा तथा यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के शिक्षक डॉ. सुशील टाया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम के अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा में निवेश के नए अवसरों पर हुई चर्चा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से शुक्रवार को सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम के अध्यक्ष श्री प्रसून मुखर्जी ने मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा में औद्योगिक निवेश, व्यापारिक सहयोग तथा सिंगापुर की कंपनियों के लिए उपलब्ध अवसरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम और सिंगापुर के निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार पारदर्शी नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में निवेश करने के लिए आने वाले निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।

बैठक के दौरान गुरुग्राम में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम का बिजनेस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में बिजनेस सेंटर स्थापित होने से सिंगापुर की कंपनियों को हरियाणा में अपने कार्यालय खोलने और निवेश करने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

इस अवसर पर सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम के अध्यक्ष श्री प्रसून मुखर्जी ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को सिंगापुर आने का आमंत्रण दिया। श्री मुखर्जी ने कहा कि सिंगापुर इंडिया बिजनेस फॉरम के निवेशक सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर हरियाणा में निवेश के अवसरों को लेकर काफी उत्साहित हैं और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अनुबंध कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

ओटीपी, मोबाइल नंबर या कर्मचारी विवरण में गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करने के आदेश

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों को सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अनुबंध कर्मचारियों के डाटा को तत्काल अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि अनुबंध कर्मचारियों के डाटा में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इनमें ओटीपी प्राप्त करने में समस्या, मोबाइल नंबर गलत होना या बदल जाना, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में त्रुटियां तथा कर्मचारियों और आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के विवरण का सही ढंग से पोर्टल पर दर्ज न होना शामिल है। सरकार ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है।

इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र अनुबंध कर्मचारियों के डाटा की जांच कर उसे प्राथमिकता के आधार पर सही करवाएं।

निर्देशों के अनुसार यदि भाग-1 या 2 के किसी पात्र अनुबंध कर्मचारी को ओटीपी या अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो संबंधित विभागाध्यक्ष मामले की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विभागों ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अद्यतन कर्मचारी पहचान संख्या, विशिष्ट वेतन कोड तथा सेवा से संबंधित पूरी जानकारी के साथ पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सही और अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए। भाग-1 के अंतर्गत आने वाले पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को भेजा जाएगा, जबकि भाग-2 के कर्मचारियों का डाटा खजाना एवं लेखा विभाग को भेजा जाएगा।

मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों को इन निर्देशों का समयबद्ध और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि सेवा सुरक्षा पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

एचएसवीपी द्वारा विकास कार्य पूरे किए बिना प्लॉट की ई-नीलामी करना गंभीर चूक : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने एक महत्वपूर्ण मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ल्रश्ढ) द्वारा किसी स्थान पर विकास कार्य पूरे किए बिना प्लॉट की ई-नीलामी करना अत्यंत गंभीर प्रशासनिक चूक है। आयोग ने कहा कि किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में डालने से पहले उस क्षेत्र के आवश्यक विकास कार्य पूरे होने चाहिए ताकि आवंटी समय पर निर्माण कार्य शुरू कर सकें।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला फरीदाबाद के सेक्टर-76/77 में ई-नीलामी के माध्यम से खरीदे गए प्लॉट से संबंधित है, जिसमें आवंटी श्री केशव शर्मा ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी कि विकास कार्य अधूरे होने के बावजूद उन्हें कब्जे का प्रस्ताव भेज दिया गया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि एचएसवीपी ने विकास कार्य पूरे किए बिना ही प्लॉट की ई-नीलामी कर दी और बाद में कब्जा देने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया, जो कि उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

आयोग ने यह भी पाया कि आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार यदि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कब्जा नहीं दिया जाता है तो एचएसवीपी को आवंटी को ब्याज देना होता है। हालांकि फरीदाबाद में कई मामलों में यह ब्याज नहीं दिया जा रहा था। आयोग के हस्तक्षेप और आदेशों के बाद ही एचएसवीपी ने ऐसे मामलों में ब्याज देना प्रारम्भ किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह भी कहा कि इस स्थिति के लिए उस समय के एस्टेट ऑफिसर या एचएसवीपी की ई-नीलामी सेल की भूमिका की जांच आवश्यक है, क्योंकि विकास कार्यों की स्थिति स्पष्ट किए बिना ही प्लॉट को नीलामी के लिए स्वीकृति दी गई। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 12 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी द्वारा संबंधित अधिकारियों को विकास कार्य दो माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद समस्या लंबे समय तक बनी रही, जो गंभीर लापरवाही को दशार्ती है।

आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि एक अन्य मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एचएसवीपी के कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि एचएसवीपी को ह्लनो प्रॉफिट-नो लॉसह्व के सिद्धांत पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन उसका आचरण कई मामलों में लाभ-केन्द्रित प्रतीत होता है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के हितों के विपरीत है। मामले में आयोग ने हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता श्री केशव शर्मा को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि एचएसवीपी द्वारा 15 दिनों के भीतर अदा की जाएगी तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट 24 मार्च 2026 तक आयोग को भेजनी होगी। आयोग ने यह भी कहा कि प्रारम्भिक रूप से यह राशि एचएसवीपी अपने कोष से दे सकता है और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी वसूली की जा सकती है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कब्जा देने की तिथि वापस लेने, वसूले गए एक्सटेंशन शुल्क की वापसी या विलंबित कब्जे पर ब्याज भुगतान जैसे मामलों में कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आयोग ने एचएसवीपी को यह भी सलाह दी है कि ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट खरीदने वाले आवंटियों के मामलों में ब्याज संबंधी नीति की समीक्षा की जाए। वर्तमान में ऐसे आवंटियों को केवल 5.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, जबकि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से प्लॉट प्राप्त करने वाले आवंटियों को तीन वर्ष बाद 9 प्रतिशत ब्याज मिलता है। आयोग का मानना है कि इस विषय में संतुलित और न्यायसंगत नीति बनाने की आवश्यकता है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि एचएसवीपी शीघ्र विकास कार्य पूर्ण कर आवंटियों को राहत प्रदान करेगा और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा।

संक्षिप्त-समाचार

बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार देना सरकार का प्रथम लक्ष्य: कैलाश सैनी

कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना सरकार का प्रथम लक्ष्य है। इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकार योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है। इतना ही नहीं राजकीय स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी शुक्रवार को देर सायं देवीदास पुरा में राजकीय पीएमश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी दीप शिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया, बच्चों को पुरस्कार वितरित किए और सरकार की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय की प्रधानाचार्या सुनीता ने विद्यालय की उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी से आग्रह करते हुए कहा कि 5 सेक्टर में विद्यालय को खाली करवाया जाए ताकि विद्यालय में बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण व कमरों की संख्या कम होने के कारण प्राइमरी विद्यालय को वहां शिफ्ट किया जा सके। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अर्पणा खंडूजा, विद्यालय प्राचार्य सुनीता देवी, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजपाल कालड़ा, नगर पार्षद राजेंद्र सैनी समाजसेवी डॉ ओमप्रकाश, मंच संचालक डॉ विजेंद्र सोलंकी व नीरज आश्री, देवीदासपुरा एस एम सी प्रधान सपना रानी, संदीप कौर, सुभद्रा रानी,रितु सोनी वर्मा, पूजा सोलंकी, वीना दुआ, शर्मिला, गीता, मोनिका, कविता रानी, सुमन रानी, मनोज कुमार और विद्यालय के सभी अध्यापक व गांव वासी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा साइकिलिंग मैराथन का आयोजन: अमन कुमार

कुरुक्षेत्र। जिला नगर आयुक्त अमन कुमार ने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकुला की तरफ से 8 मार्च को सुबह 7 बजे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणू भाटिया शिरकत करेंगी। डीएमसी अमन कुमार ने कहा कि 8 मार्चरविवार को साइकिलिंग मैराथन में लगभग 1500 छात्राओं के भाग लेने की संभावना है। इस मैराथन को सफल बनाने के लिए जिला नगर आयुक्त संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके आवश्यक प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस मैराथन के लिए कार्यक्रम स्थल एवं साइकिलिंग मार्ग का पूर्व निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी स्वच्छता, पेयजल, अस्थाई शौचालय, बैरीगेटिंग, मंच सहित अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे, पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ चर्चा करने के बाद कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सड़क एवं साइकिलिंग मार्ग की मरम्मत, चिकित्सा व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, स्वच्छता एवं पेयजल, बिजली की आपूर्ति व्यवस्था के साथ-साथ अग्निशमन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी समय रहते तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने घोषित किए 20 परीक्षाओं के परिणाम

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (केयू) ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की 20 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंकेश्वर प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि इन परिणामों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां विद्यार्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें दिसम्बर 2025 में आयोजित बी.एससी. (फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स) 5वां सेमेस्टर, बीएचएमसीटी 7वां सेमेस्टर (फ्रेश/री-अपीयर) नॉन-सीबीसीएस, बीटेक 8वां सेमेस्टर (सीएसई), बी.एससी. (इंटीरियर डिजाइनिंग) पहला सेमेस्टर, बी.एससी. (इंटीरियर डिजाइनिंग) 5वां सेमेस्टर, डिप्लोमा इन योगा एंड एप्लाइड फिलॉसफी प्रथम सेमेस्टर, एम.टेक (एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट) प्रथम सेमेस्टर, बीसीए 5वां सेमेस्टर (री-अपीयर), बी.एससी. (होम साइंस) तीसरा सेमेस्टर, बी.ए. 5वां सेमेस्टर (री-अपीयर), बी.वोक इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, बी.ए. (एमसी) प्रथम सेमेस्टर (री-अपीयर) नॉन-सीबीसीएस तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग पहला सेमेस्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया मई 2025 में आयोजित बी.टेक चतुर्थ सेमेस्टर (सिविल) आईयूएमएस, बी.टेक चतुर्थ सेमेस्टर (सीएसई) आईयूएमएस, बी.टेक चतुर्थ सेमेस्टर (केमिकल, बायोटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल) बी.टेक चतुर्थ सेमेस्टर (कंप्यूटर इंजीनियरिंग/आईटी), बी.टेक चतुर्थ सेमेस्टर (ईई, ईईई, ईसीई) आईयूएमएस, बी.एससी. (ऑनर्स) गणित दूसरा सेमेस्टर तथा बीएएलएलबी (ऑनर्स) छठा सेमेस्टर कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को परिणाम से संबंधित कोई समस्या आती है तो वे परीक्षा शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में 7 से 11 मार्च तक आयोजित होगा इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक 2026

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के तत्वावधान में कल 7 से 11 मार्च 2026 तक चंडीगढ़ में प्रथम ₹इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक 2026₹ का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश-विदेश के न्यायिक और कानूनी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ भाग लेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम में भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत बनाना तथा इस क्षेत्र में संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 7 मार्च को शाम 5 बजे हयात रीजेंसी में आयोजित होगा।

संपादकीय

मिडिल ईस्ट जंग का असर भारत की रसोई तक ! गैस संकट टालने को सरकार का बड़ा कदम

मध्य-पूर्व में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात अब सीधे भारत की रसोई तक पहुँचने लगे हैं। अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर दबाव पैदा हो गया है। तेल और गैस की आपूर्ति में संभावित व्यवधान को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए आपात शक्तियों का इस्तेमाल किया है और देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो और करोड़ों परिवारों को किसी संकट का सामना न करना पड़े। दरअसल, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है और उसकी कुल मांग का लगभग दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा होता है। इनमें भी लगभग 85 से 90 प्रतिशत आपूर्ति पश्चिम एशिया से आती है। ऐसे में यदि क्षेत्रीय संघर्ष लंबा खिंचता है या समुद्री मार्गों में बाधा आती है तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार ने समय रहते स्थिति को संभालने के लिए उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया है। भारत में एलपीजी केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि करोड़ों घरों की रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 33 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उज्ज्वला जैसी योजनाओं के कारण रसोई गैस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसलिए आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर असर डाल सकती है। यही कारण है कि सरकार ने एलपीजी को 'आवश्यक घरेलू ईंधन' मानते हुए इसे प्राथमिकता देने का सला किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी तेल रिफाइनरियों को उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन का अधिकतम उपयोग एलपीजी उत्पादन के लिए करना होगा। साथ ही इन गैसों को पेट्रोकेमिकल उद्योग में इस्तेमाल करने पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। इसके अतिरिक्त उत्पादित एलपीजी को मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियों – इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम – के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि यह फैसला ऊर्जा उद्योग के लिए आसान नहीं है। प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादों और गैसोलीन मिश्रण बनाने में भी होता है, जिनकी बाजार कीमत अधिक होती है। इसलिए एलपीजी उत्पादन के लिए इन कच्चे पदार्थों को मोड़ने से कुछ उद्योगों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा संकट में घरेलू जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा संकट केवल एलपीजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की व्यापक ऊर्जा निर्भरता को भी उजागर करता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। तेल और गैस के मामले में पश्चिम एशिया भारत के लिए सबसे बड़ा आपूर्ति स्रोत रहा है। ऐसे में यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है और समुद्री मार्ग – विशेष रूप से होरमुज जलडमरूमध्य – प्रभावित होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। होरमुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए यह मार्ग और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अधिकांश ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र से आते हैं। यदि किसी सैन्य टकराव के कारण यह मार्ग अस्थायी रूप से भी बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और भारत जैसे आयातक देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत अब ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर भी जोर दे रहा है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों से एलपीजी और एलएनजी खरीदने की संभावनाओं पर काम कर रही है। साथ ही रणनीतिक भंडार बढ़ाने और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल देश में ऊर्जा भंडार पर्याप्त हैं और तत्काल किसी संकट की स्थिति नहीं है। तेल कंपनियों ने भी आश्वासन दिया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। फिर भी वैश्विक स्थिति को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार बेहद संवेदनशील होता है और भू-राजनीतिक घटनाओं का उस पर तुरंत असर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने और आयात स्रोतों में विविधता लाने से ही भविष्य के ऐसे संकटों से बचा जा सकता है।दरअसल, ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी बाहरी संकट का असर सीधे रसोई तक पहुंचने लगे तो यह संकेत है कि ऊर्जा आपूर्ति तंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है। मध्य-पूर्व का मौजूदा संघर्ष चाहे जितने समय तक चले, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति और आम आदमी की रसोई के बीच दूरी बहुत कम रह गई है। इसलिए भारत के लिए यह समय केवल संकट प्रबंधन का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाने का भी है।

मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओं से सशक्त होंगी महिलाएं

प्रद्युम्न शर्मा (हि.स)

हर वर्ष आठ मार्च को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों, समानता और सम्मान के संघर्ष का प्रतीक है। यह दिन समाज को यह याद दिलाने का अवसर भी है कि महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। इसी सोच को व्यवहार में उतारने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने इस विशेष प्रसंग के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया है। इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना और स्थानीय स्तर पर ठोस निर्णय लेना है।

मध्यप्रदेश में पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायतों के पंचवर्षीय कार्यकाल में निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिशत पचास से भी अधिक, लगभग बावन प्रतिशत है। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे अब केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को सार्थक और प्रभावी बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इन्हीं महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कंधों पर है। यदि वे सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं, तो ग्राम स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति संभव है।

यदि हम एक नजर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डालें तो इसका इतिहास महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महिला श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य कार्य के बेहतर घंटे, उचित पारिश्रमिक और समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना था। धीरे-धीरे यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर फैल गया और महिलाओं के अधिकारों की आवाज मजबूत होती गई। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और उसी वर्ष आठ मार्च को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। तब से यह दिन दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर सामने आता है कि क्या महिला पंचायत प्रतिनिधि वास्तव में स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। कई स्थानों पर महिलाएं सक्रिय रूप से पंचायत के कार्यों में भाग ले रही हैं और विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, किंतु कुछ जगहों पर अभी भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य पंचायत के निर्णय लेते हैं और कार्यों का संचालन करते हैं। इसे प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कहा जाता है। यह स्थिति महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। उन्हें योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानूनों की जानकारी देकर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना जरूरी है।

महिला सशक्तिकरण के लिए समाज की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना समय की मांग है। आज महिला साक्षरता पहले की तुलना में काफी आगे बढ़ी है, किंतु सिर्फ साक्षरता ही पर्याप्त नहीं। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक सम्मान मिलना भी जरूरी है। साथ ही पारंपरिक सामाजिक सोच और पुरुषों के अनावश्यक हस्तक्षेप को भी कम करना होगा, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बन सकें।

ग्राम सभाएं ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती हैं। यही वह मंच है जहां गांव के विकास से जुड़े निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित विशेष ग्राम सभाएं महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्रभावी मंच बन सकती हैं। इन सभाओं में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ गांव की अन्य महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं पर भी खुलकर चर्चा की जा सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर समाधान खोजने और महिलाओं के हित में ठोस निर्णय लेने का अवसर मिलता है।

इन विशेष ग्राम सभाओं को प्रेरणादायक और परिणामकारी बनाने के लिए कई सकारात्मक पहलें की जा सकती हैं। गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को सम्मानित किया जा सकता है, जिससे अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं की आजीविका, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण संकल्प लिए जा सकते हैं।

ग्राम सभाओं की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि गांव की अधिक से अधिक महिलाएं इसमें भाग लें। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राम सभा के आयोजन की सूचना गांव की सभी महिलाओं तक पहुंचे। महिला स्वसहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन ग्राम सभाओं में महिलाओं को उनके अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी देना भी अत्यंत आवश्यक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी देकर महिलाओं को जागरूक बनाया जा सकता है। इसके साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण मिशन और वन स्टॉप सेंटर जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन ग्राम सभाओं में कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इनमें बाल विवाह की रोकथाम, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण, धात्री माताओं की देखभाल, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और किशोरियों के उपचार तथा व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं में महिला हितग्राहियों को प्राथमिकता मिले।

यदि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इन विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायतें महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लें और उसे व्यवहार में भी लागू करें, तब जरूर ये उम्मीद दिखाई देती है कि आने वाले समय में कई ग्राम पंचायतें

महिला हितैषी ग्राम पंचायत' के रूप में विकसित हो सकती हैं।

(लेखक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक हैं)

आज का राशिफल

मेष: आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े कार्यों को आप निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या उच्च पद भी मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपके मन में कई नए विचार उभर सकते हैं, जिनका उपयोग आप भविष्य की योजनाओं या नए व्यवसाय में कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के व्यवहार से थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज आप अपने आत्मविश्वास और व्यवहार के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के इच्छुक जोड़ों को परिवार की सहमति मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज आप मानसिक थकान दूर करने के लिए कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, गले में संक्रमण या सर्दी-जुकाम जैसी परेशानी हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। दृढ़ निश्चय और मेहनत के दम पर आप किसी महत्वपूर्ण काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। हालांकि वित्तीय मामलों या निवेश से जुड़े कार्यों में थोड़ी देरी संभव है। लोन या आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: व्यापार और पेशेवर जीवन में आज आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल हो सकते हैं। काम की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार दिखाई देगा। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अत्यधिक उत्साह या जल्दबाजी के कारण कार्यों में बाधा आ सकती है। पुराने स्वास्थ्य संबंधी रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही न करें। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आज घर में किसी शुभ कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होने की संभावना है, जिससे पारिवारिक माहौल आनंदमय रहेगा। पैतृक व्यवसाय या संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी बनाई योजनाएं सफल हो सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

मकर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरूआत के लिए दिन अनुकूल माना जा रहा है। यदि कोई कानूनी मामला लंबित है तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा। पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में चल रही किसी भी असहमति को आप बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। नई तकनीक, ज्ञान या कौशल सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

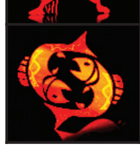
मीन: आज स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के कारण दवाइयों पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट पर थोड़ा दबाव महसूस होगा। घर या कार्यस्थल पर किसी जरूरी वस्तु की कमी से आप थोड़े परेशान या चिड़चिड़े हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें। *(सिटी दर्पण)*

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना: किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जनऔषधि परियोजना का रणनीतिक विकास

जगत प्रकाश नड्डा

किसी राष्ट्र की प्रगति का असली पैमाना अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि उसके नागरिक स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। दशकों तक, भारत के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए दवाओं की उच्च लागत एक प्रमुख वित्तीय बाधा रही है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है।यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करके एक व्यापक और व्यवस्थित परिवर्तन लाने में सफल रही है।

वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयाँ सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्वभर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80-90% है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयाँ पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं।

पीएमबीजेपीकेवल एक खुदरा-बिक्री कार्यक्रम नहीं है; यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दशार्ता है। यह इस साल के जनऔषधि सप्ताह के थीम में परिलक्षित होता है, 'जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ', यह थीम लाखों लाभार्थियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से, योजना ने सुनिश्चित किया है कि दवाइयाँ बाजार दरों की तुलना में 50% से 80% तक की कम कीमतों पर उपलब्ध हों और सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों को समर्थन प्रदान करती हों। क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि लाभार्थी लागत बचत और दवाइयों तक बेहतर पहुँच की सराहना करते हैं।

योजना का पैमाना इसके उत्पाद संग्रह से भी परिलक्षित होता है। जनऔषधि 2,110 दवाओं और 315 सर्जिकल उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है, जो 29 विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों को शामिल करती है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के प्रत्यक्ष देखरेख में,संग्रह का विस्तार एक गतिशील, डेटा-संचालित प्रक्रिया है, जिसमें बाजार विश्लेषण, हितधारकों की भागीदारी और एक समर्पित विशेषज्ञ समिति की कठोर निगरानी शामिल हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना देश की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधीय मांगों के अनुरूप विकसित होती रहे।

कठोर नियामक निरीक्षण के साथ, भारतीय दवा कंपनियां 200 से अधिक देशोंके लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन गई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। भारतीय दवा कंपनियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोपजैसे उभरते बाजारों में भी विस्तार कर रही हैं।

यह उद्योग जैविक दवाओं के समान दवाओं (बायोसिमिलर), जैविक दवाओं के जेनेरिक प्रतिरूपों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही जटिल जेनेरिक और विशेष दवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी अधिक निवेश कर रहा है। ये दूरदर्शी कार्यक्रम भारत को न केवल एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में, बल्कि किफायती दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के नवाचार अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करते हैं।

गुणवत्ता बनाम मूल्य पर बहस कभी-कभी सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। एक बहु-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से,पीएमबीजेपी ने इस मिथक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है कि किफायती होना निर्माण मानकों में समझौते का संकेत देता है। दवाइयाँ डब्ल्यूएचओ-जीएमपीप्रमाणित निमार्ताओं से खरीदी जाती हैं, जो वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं। नियम निर्धारित करते हैं कि फामेर्सी की शेल्फ तक पहुंचने सेपहले दवा के हर बैच काराष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में सख्त सत्यापन होना आवश्यक है। ये दवाइयाँ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940के नियमों का पालन करती हैं और ब्रांडेड विकल्पों के सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों के अनुरूप हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद से पहले सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और खरीद के बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पीएमबीआई नियमित रूप से दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और समीक्षा करती है, ताकि स्थापित विनियमों के पालन में कोई कोताही न होना सुनिश्चित किया जा सके।

एक आईटी-संचालित वितरण नेटवर्क, जिसे पांच अत्याधुनिक भंडार गृहों और देशभर के में 41 विशेष वितरकों का समर्थन प्राप्त है,ने सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ सुदृढ़ बनी रहे।

तीन स्तंभों -पहुँच, गुणवत्ता और सस्ती कीमत - पर ध्यान केंद्रित करके, पीएमबीजेपी ने लाखों लोगों के चिकित्सा खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। निरंतर संस्थागत समर्थन, लोगों की बढ़ती जागरूकता और अवसंरचनात्मक सुधारों के साथ, हर जिले में जनऔषधि केंद्र का सपना अब दूर की आकांक्षा नहीं, बल्कि यह ठोस रूप ले चुका है और वास्तविकता के करीब है।

ह्यविकसित भारत @2047' दृष्टि के तहत मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर किसी के लिए एक सुदृढ़, न्यायसंगत और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई जाए। इसमें बेहतर अस्पताल, कम चिकित्सा खर्च, उपचार तक आसान पहुंचऔर सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हैं। बहु-क्षेत्रीय सहयोगों के जरिये, पीएमबीजेपी ने यह साबित किया है कि सही संस्थागत दृष्टि के साथ, स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह परियोजना प्रगति करती रहे और किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर बनाए रखे।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

एआइ, क्वांटम और सेमी कंडक्टर्स से लेकर ऊर्जा व खनिज तक, व्यापक है भारत-कनाडा अनुबंध

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारत और कनाडा के रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा दी है। भारत के चार दिवसीय दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ हुई वाताओं में जिस तरह से भविष्य की तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और व्यापार विस्तार पर ठोस समझौते हुए, वे 21वीं सदी की वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को और मजबूत करने वाले कदम हैं।

यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब दुनिया तकनीकी क्रांति, ऊर्जा संक्रमण और सप्लाई चेन संकट के दौर से गुजर रही है। इसलिए भारत और कनाडा के बीच हुआ यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से बेहद अहम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई यह बात कि 'हमारी पहली बैठक में ही दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है,' पिछले कुछ वर्षों में रिश्तों में आई ठंडक को पिघलाने की एक गंभीर कोशिश का रूप में साफ दिखाई देती है।

कहना होगा कि भारत और कनाडा दोनों लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार और बहुलतावादी समाज में विश्वास रखने वाले देश हैं। दोनों का साझा विजन 'मानवता की भलाई' है। इसी साझा सोच को अब 'नेक्स्ट पार्टनरशिप' यानी भविष्य की रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश की जा रही है। साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य इस दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है।

भारत और कनाडा के बीच हुए समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी असर डालने वाला पक्ष है, भविष्य की तकनीकों में सहयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरकंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स

जैसे क्षेत्रों में साझेदारी, भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज दुनिया नई तकनीकी दौड़ में शामिल है, जहां डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और चिप निर्माण ही शक्ति संतुलन तय कर रहे हैं। अमेरिका-चीन टेक वॉर के बीच भारत के लिए यह अवसर है कि वह विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में उभरे। कनाडा इस क्षेत्र में शोध, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में मजबूत स्थिति रखता है, जबकि भारत के पास विशाल टैलेंट पूल और तेजी से बढ़ता डिजिटल बाजार है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स और निजी उद्योगों को जोड़ने की योजना भारत के न्यू स्पेस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसरो की सफलताओं के बाद भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। कनाडा के साथ साझेदारी से तकनीक, फंडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान होगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ ही भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में हुआ सहयोग भारत-कनाडा संबंधों का दूसरा बड़ा स्तंभ है। हाइड्रोकार्बन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों दोनों के लिए अहम है। वस्तुतः भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं कनाडा के पास प्राकृतिक संसाधनों और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विशाल भंडार है। दोनों देशों के सहयोग से ऊर्जा आपूर्ति स्थिर होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भी ठोस प्रगति संभव होगी।

'भारत-कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज समिट' का आयोजन इस साझेदारी को व्यावहारिक धरातल पर उतारने का मंच बनेगा। इसके साथ ही कनाडा का अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस (क्रअ) और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होना, भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करता है।

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का महत्व किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति को तय करता है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरण इन्हीं पर निर्भर हैं। कनाडा इन खनिजों का बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत इनका बड़ा उपभोक्ता बनने जा रहा है। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ टङ्मव भारत की सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत को अपनी ग्रीन एनर्जी व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजनाओं के लिए स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यह अनुबंध रणनीतिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि भविष्य की लड़ाइयाँ संसाधनों और तकनीक पर आधारित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताया गया कि कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, यह भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक विश्वास का बड़ा संकेत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में यह निवेश रोजगार सृजन और विकास की गति को तेज करेगा।

सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जॉइंट पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हुए समझौते कृषि, खाद्य सुरक्षा और व्यापार संतुलन को मजबूत करेंगे। इससे किसानों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा। अतः इन तथ्यों के आधार पर आज यही कहना होगा कि भारत-कनाडा अनुबंध को सिर्फ द्विपक्षीय नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति को और मजबूत करती है। पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध भारत को एक भरोसेमंद, स्थिर और लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में स्थापित करते हैं। इसके साथ ही यह सहयोग भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को भी मजबूती देता है, जहां वह अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा के साथ मिलकर एक संतुलित वैश्विक ढांचा तैयार कर रहा है।

पंजाब सरकार रंगला पंजाब के सपने को साकार करने के लिए सेवा और विकास के प्रति संकल्पित: गुलाब चंद कटारिया

881 आम आदमी क्लीनिकों में मुफ्त दवाइयाँ और टेस्ट; ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 4.7 करोड़ दर्ज: गुलाब चंद कटारिया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राज्य सरकार की पंजाब और पंजाबियों के प्रति समर्पित भावना और ईमानदारी से सेवा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार एक गतिशील और प्रगतिशील रंगला पंजाब के निर्माण के उद्देश्य से राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भावना के साथ कार्य कर रही है।

16वीं पंजाब विधानसभा के बारहवें बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, शासन व्यवस्था, जनकल्याण, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में पंजाब सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, पंजाब सरकार एक मजबूत, समग्र और जन-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 23 जिला अस्पतालों, 42 उप-डिवीजनल अस्पतालों, 162 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 523 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 881 आम आदमी क्लीनिकों और 2453 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। यह व्यवस्था राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने आगे कहा, पंजाब भर में 881 आम आदमी क्लीनिकों में 107 प्रकार की दवाइयाँ और 47 प्रकार के टेस्ट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक ओपीडी में 4.7 करोड़ से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें 1.55 करोड़ गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल हैं। वर्ष 2025झ26 में यह संख्या दो करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 240 नए आम आदमी क्लीनिक जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

राज्यपाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों में शुरू की गई मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं ने मातृ मृत्यु दर को 105 से घटाकर 90 करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। इसके अलावा, इन क्लीनिकों में रेबीज विरोधी टीकाकरण सेवाएं भी शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूती पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा, पंजाब सरकार ने इतिहास में डॉक्टरों की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की है। वर्ष 2022 से अब तक सरकारी अस्पतालों के लिए 934 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो वर्तमान में राज्य में कार्यरत कुल डॉक्टरों का लगभग 25 प्रतिशत है।

उन्होंने आगे कहा, पंजाब सरकार लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जो विशेषज्ञ सेवाओं के सबसे बड़े विस्तार को दशार्ता है। इसी प्रकार 400 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि 500 अतिरिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। व्यापक स्वास्थ्य कवरेज का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लागू की है। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 2356 मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब और चंडीगढ़ में ऐसे अस्पतालों की संख्या लगभग 900 है।

उन्होंने आगे कहा, इस योजना के तहत प्रत्येक पंजाबी को कैशलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरिश्ते और सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरूआत की है। फरिश्ते योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले परोपकारी नागरिकों को 2,000 रुपये और प्रशंसा प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। इस पहल के माध्यम से अब तक 600 से अधिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता मिल चुकी है। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास

का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज को शुरू करके उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल की है। दिसंबर 2025 में पहले सफल लिवर ट्रांसप्लांट के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा, मई 2026 से सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, सीएम दी योगशाला एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न शहरों में प्रतिदिन लगभग 5000 प्रशिक्षकों की निगरानी में योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग भाग लेते हैं। नशे की समस्या पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की समस्या और तस्करी से निपटने के लिए युद्ध नशों विरुद्ध अभियान शुरू किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस अभियान के तहत नशा मुक्ति सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पूरे पंजाब में 548 ओओटी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उपचार और पुनर्वास के लिए 36 सरकारी तथा 177 निजी नशा मुक्ति केंद्र, और 19 सरकारी तथा 74 निजी पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं। कैदियों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 19 जेलों में भी नशा मुक्ति सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल की शुरूआत से अब तक 10.63 लाख से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उपचार प्रदान किया गया है।

कैंसर रोगियों को दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 957 करोड़ रुपये की राशि से 74,000 से अधिक कैंसर मरीजों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। आपदा प्रबंधन के संबंध में उन्होंने बताया कि हाल ही में आई बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक मेडिकल कैंप और विशेष जनस्वास्थ्य अभियान चलाए गए थे। इन अभियानों के अंतर्गत फॉगिंग, आशा वर्करों द्वारा घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और दवा किटों का वितरण शामिल था। इसके अतिरिक्त 2300 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 8 लाख से अधिक मरीजों की जांच की गई, ताकि संकट की स्थिति में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा सुधारों को रेखांकित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत अप्रैल 2022 से अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पांच दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों के सात बैचों को सिंगापुर, 199 हेडमास्टरों के चार बैचों को आईआईएम अहमदाबाद तथा 144 प्राथमिक कैडर शिक्षकों के दो बैचों को तुर्कू (फिनलैंड) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। स्कूलों में सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिंचाई और कृषि के विषय में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सभी किसानों तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 787 करोड़ रुपये के निवेश से 3,443 किलोमीटर नए खालों और भूमिगत पाइपलाइनों के निर्माण की योजना बनाई है। इनमें से 2,650 किलोमीटर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने 4,557 करोड़ रुपये की लागत से 2,600 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप पहली बार लगभग 1,365 स्थानों तक नहरी पानी पहुंच सका है, जिनमें से 465 स्थानों तक वर्ष 2025 में पानी पहुंचाया गया। लंबे समय से लंबित सरहिंद फीडर नहर की रीलाइनिंग परियोजना भी अब पूरी हो चुकी है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आगे बताया कि कंडी क्षेत्र के अर्ध-पर्वतीय इलाकों को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने 28 नई लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 15 योजनाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। किसानों को दी जा रही सहायता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त खरीफ (सावनी) मौसम में मक्का के रकबे को बढ़ाने के लिए पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 17,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने इस वर्ष गन्ने के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। आगामी पेराई सत्र के लिए राज्य सरकार 416 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य दे रही है, जो देश में गन्ना किसानों को दी जाने वाली सबसे अधिक कीमत है।

राज्यपाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 33.96 करोड़ रुपये मूल्य का 84,889.7 क्विंटल गेहूं का बीज और 65.15 लाख रुपये मूल्य का 620.5 क्विंटल सरसों का बीज निःशुल्क वितरित किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा देने के लिए वर्ष 2025-26 में 9,992 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में बागवानी के टिकाऊ विकास के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 1,300 करोड़ रुपये का परियोजना प्रगति पर है, जो क्लस्टर स्तर पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना और बदलते जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी फसलों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 12,597 करोड़ रुपये की कुल लागत से 40,103 किलोमीटर टूटी या क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों के उन्नयन और आधुनिकीकरण की परियोजना चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड ने 350.25 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है और 12 दिसंबर 2025 तक 220.54 करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वर्ष 2025-26 में रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग ने 959 प्लेसमेंट कैंपों और रोजगार मेलों के माध्यम से 48,912 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

खेलों के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2025-26 में खेलों के लिए 362.24 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। खेल विभाग द्वारा 10,406 खिलाड़ियों को खेल उपकरणों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 12.15 करोड़ रुपये, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली खिलाड़ियों और उनके कोचों को 4.91 करोड़ रुपये, तथा अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं और जूनियर-सीनियर प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1060 खिलाड़ियों को 23.1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला के लिए वर्ष 2025-26 में 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है तथा पंजाब भर में 3,100 खेल मैदानों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। निवेश और औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 8,261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 1,50,817 करोड़ रुपये के निवेश और करीब 5,31,619 लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी के विदेशी कारोबारियों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों के कारोबारियों से सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है। उद्योग क्रांति पहल के हिस्से के रूप में पंजाब सरकार ने 2025 में 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन भी किया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यह भी कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में 606 गांवों को कवर करने वाले 15 बड़े सतही जल परियोजनाओं में से सात को चालू किया है, जिनकी लागत 519.88 करोड़ रुपये है। इससे 7.37 लाख आबादी को लाभ होगा और सभी 15 परियोजनाएं पूरी होने पर लगभग 25 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने दिसंबर 2025 तक के बकाए सहित सभी बिजली सब्सिडी बकाए सफलतापूर्वक निपटा दिए हैं। पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड मजबूत जनता निगरानी के साथ निजी निवेश और विशेषज्ञता को एकीकृत करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पदार्फाश; नाबालिग समेत छह व्यक्ति पांच पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पांच आधुनिक पिस्तौलों और एक तेजधार हथियार समेत छह व्यक्तियों, जिनमें एक नाबालिग है, को गिरफ्तार कर सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रोहित कुमार (18) निवासी मकबूलपुरा, अमृतसर; करनबीर सिंह उर्फ अजय (24) निवासी गांव काले तरनतारन; जश्नदीप सिंह उर्फ ज्ञानी (18), ओंकार सिंह उर्फ वंश (21) और आकाशदीप सिंह (24), तीनों निवासी गांव मरी मेघा, तरनतारन तथा 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। बरामद किए गए हथियारों में एक .30 बोर, एक 9 एमएम ग्लॉक, एक .30 बोर पीएक्स5, एक 9 एमएम टॉरस और एक 9 एमएम ग्रेटा (पाकिस्तान में निर्मित) तथा 34 जिंदा कारतूस शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियारों की खेप प्राप्त करते थे। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी व्यक्ति अपने हैंडलरों के निर्देश पर हथियारों की खेप प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति करते थे। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पदार्फाश करने के लिए इस मामले में आगे-पीछे का पता लगाने के लिए जांच जारी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कार्रवाई के संबंध में विवरण साझा करते हुए कहा कि गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने रोहित कुमार को एक नाबालिग समेत काबू कर उनके कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक तेजधार हथियार बरामद किया।

कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार यह साबित करता है कि वे पंजाब की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते: कैबिनेट मंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ईटीओ ने कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। कैबिनेट मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि विपक्ष का सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने वाला रवैया और अनावश्यक नारेबाजी राज्य सरकार की विकासात्मक पहलों से लोगों का ध्यान भटकाने की उनकी हताश कोशिशों का हिस्सा है। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार को राज्य के खजाने या उसके लोगों की भलाई पर ध्यान देने के बजाय शराब, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने राज्य के संसाधनों की लूट की अनुमति दी, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने

वित्तीय अनुशासन और राज्य के वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जो दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में पहले ही हाशिये पर जा चुकी है, अब अपने जनविरोधी और दलित विरोधी रुख के कारण आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी को दो बार बैठने, भाषण सुनने और चर्चा के दौरान अपना जवाब देने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार यह साबित करता है कि उन्हें संवैधानिक मयार्दाओं की कोई परवाह नहीं है। अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोग भली-भांति जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का उदाहरण देते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहले सिविल सेवा परीक्षा पास की और बाद में जनता की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे योग्य व्यक्ति की तुलना बैंड-बाजे से करने की हिम्मत की, जो पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज जब उनके साथियों ने अपने साथ बैंड-बाजे वाले लाकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कांग्रेसी नेता भड़क उठे, क्योंकि वे अपने ही अहंकार की सच्चाई का सामना नहीं कर सके। इस दौरान आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा में आज कांग्रेस का रवैया एक शर्मनाक कृत्य है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक की कटौती, व्यावसायिक दरों में 79 पैसे तक और औद्योगिक दरों में 74 पैसे तक की कटौती का लाभ

पंजाब के घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब भर में घरों, कारोबारों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे प्रति यूनिट और औद्योगिक इकाइयों के लिए 74 पैसे प्रति यूनिट तक कम की गई हैं। पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता और सदस्य रविंदर सिंह सैनी (सदस्य तकनीकी) तथा रवि कुमार (सदस्य कानूनी) की मौजूदगी में जारी किया गया नया टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू हो जाएगा। इस फैसले को बड़ा जन-हितैषी कदम करार देते हुए बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ में कटौती से घरेलू उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी, एम.एस.एम.ई. मजबूत होंगे और पंजाब में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ई.वी. चार्जिंग टैरिफ को 5 रुपये प्रति यूनिट तक कम किया गया है, जो देश में सबसे कम है, साथ ही पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वित्तीय सुधारों के साथ, जिसने ए+ रेटिंग प्राप्त की है और 2634 करोड़ का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुशल अगुवाई के तहत पंजाब के बिजली क्षेत्र की बढ़ती दक्षता की मुखर तस्वीर है। संशोधित टैरिफ ढांचे से बिजली क्षेत्र की वित्तीय मजबूती के साथ-साथ उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बिजली मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को खपत स्लैब के आधार पर प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक की कटौती,

व्यावसायिक संस्थानों को प्रति यूनिट 79 पैसे तक की कटौती का लाभ और औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 74 पैसे तक की कटौती की राहत मिलेगी। मीडिया से बातचीत में बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई के तहत पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिजली दरें उपभोक्ता-अनुकूल रहें और राज्य में औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को भी बल मिले। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली पहल के माध्यम से राज्य के लोगों को पहले की तरह काफी सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने कहा, प्रति माह 300 यूनिट बिजली, और जो प्रति बिलिंग साइकिल 600 यूनिट है, के माध्यम से घरों के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घर पहले ही भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त कोटे से अधिक खपत करने वाले घरों के लिए भी, टैरिफ घटा दिए गए हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, 300 यूनिटों से अधिक खपत के लिए, टैरिफ में प्रति यूनिट 0.70 रुपये की कटौती की गई है, जिससे अधिक खपत वाले घरों को भी काफी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज भी घटा दिए हैं। 2 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये प्रति किलोवाट, जबकि 7 किलोवाट से 20 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 10 रुपये प्रति किलोवाट घटा दिए गए हैं।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, 7 किलोवाट तक लोड वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए, 500 यूनिटों तक खपत के लिए टैरिफ में 0.79 रुपये प्रति यूनिट और 500 यूनिटों से अधिक खपत के लिए 0.65 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है। पीएसपीसीएल संचालन दक्षता और वित्तीय प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य लक्ष्यों में वितरण घाटे को लगभग 20 प्रतिशत घटाना, बेहतर योजना और खरीद के माध्यम से बिजली खरीद लागतों को कम करना, और बिजली मिश्रण में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाना शामिल है। ये कदम पीएसपीसीएल की वित्तीय सेहत को और मजबूत करेंगे, समय के साथ सब्सिडी निर्भरता को घटाएंगे और पंजाब के लोगों के लिए विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जन कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह पंजाब में औद्योगिक विकास और निवेश का समर्थन करते हुए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए काम करना जारी रखेगा।

संक्षिप्त-समाचार

इनड्राइव ने चंडीगढ़ में लॉन्च की राइड एक्सएल कैटेगरी

चंडीगढ़। अपने फेयर-प्राइस मॉडल और यूजर-फर्स्ट अप्रोच के लिए जाना जाने वाला वैश्विक मोबिलिटी और अर्बन सर्विसेज प्लेटफॉर्म इनड्राइव ने चंडीगढ़ में इनड्राइव राइड एक्सएल लॉन्च करने की घोषणा की। नई कैटेगरी में ज्यादा स्पेस वाले 6-सीटर वाहन शामिल किए गए हैं, जिन्हें ग्रुप ट्रैवल, फैमिली आउटिंग, एयरपोर्ट ट्रांसफर और इंटरसिटी यात्राओं को अधिक आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यात्री ड्राइवर के साथ सीधे बातचीत कर किराया तय कर सकते हैं और दोनों की सहमति से एक उचित किराए पर सफर कर सकते हैं। नई इनड्राइव राइड एक्सएल कैटेगरी में ज्यादा स्पेस वाले 6-सीटर वाहन शामिल हैं, जिनमें एक्स्ट्रा लेगरूम, एयर-कंडीशन्ड केबिन और पर्याप्त लगेज स्पेस उपलब्ध है। इससे छह यात्रियों तक के लिए बिना कई गाड़ियाँ बुक किए आराम से साथ यात्रा करना आसान हो जाता है। इसलिए एक्सएल राइड्स परिवारों, दोस्तों के समूह, ऑफिस आउटिंग, सामान के साथ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और सुविधाजनक ग्रुप ट्रैवल की तलाश में रहने वाली बिजनेस टीमों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं। इनड्राइव के फेयर प्राइस मॉडल के अनुसार यात्री अपना किराया प्रस्तावित कर सकते हैं और कई ड्राइवरों के ऑफर में से चुन सकते हैं, जिससे ट्रांसपरेंसी बनी रहती है और दोनों पक्षों की सहमति से किराया तय होता है, साथ ही यात्रियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। चंडीगढ़ जैसे शहर में, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार है, एक्सएल राइड्स लंबी दूरी और इंटरसिटी यात्रा के लिए भी एक आरामदायक और प्रैक्टिकल विकल्प प्रदान करती हैं।

सैमसंग ने एडवांस्ड गैलेक्सी बड्स4 प्रो लॉन्च किया

चंडीगढ़। भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, सैमसंग ने घोषणा की है कि उसके गैलेक्सी बड्स4 प्रो और गैलेक्सी बड्स4 आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। ये नए ईयरबड्स बेहतरीन हाई-फाई ऑडियो और रोजमर्रा के इस्तेमाल के अनुभव को फिर से परिभाषित करते हैं। गैलेक्सी बड्स4 सीरीज शानदार साउंड क्वालिटी और कम्प्यूटेशनल तरीके से तैयार की गई फिटिंग का एक बेजोड़ मेल है। पहली बार, बड्स4 प्रो में ज्यादा चौड़ा वूफर, बेहतर ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और बेहतर एडेप्टिव इक्वलाइजर दिया गया है, जिससे आवाज मूल रिकॉर्डिंग जैसी शुद्ध सुनाई देती है। इसमें अकका गहरा इस्तेमाल सैमसंग की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है, जिसके तहत ईयरबड्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग दिन भर कैसे सुनते हैं, कैसे चलते-फिरते हैं और कैसे रहते हैं। बड्स4 सीरीज के साथ, सैमसंग ने नए ₹ब्लेड डिजाइन₹ को पेश किया है। यह एक बड़ी कम्प्यूटेशनल उपलब्धि है, जो दुनिया भर के लाखों लोगों के कानों के डेटा पॉइंट्स और 10,000 से अधिक सिमुलेशन पर आधारित है। बड्स4 सीरीज में एक अल्ट्रा-स्लीक और एर्गोनॉमिक फिट दिया गया है, ताकि उपयोगकर्ताओं को अधिक आरामदायक अनुभव मिले।

सनावर अल्मनाई पीसीए मुल्लांपुर में 8वें राजेश पुरी मेमोरियल इंटर-हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 की मेजबानी करेंगे

चंडीगढ़। द ओल्ड सनावरियन सोसाइटी (ओएसएस), जो द लॉरेंस स्कूल, सनावर की ऑफिशियल ओल्ड स्टूडेंट्स (अल्मनाई) एसोसिएशन है, 7 और 8 मार्च को मशहूर पीसीए स्टेडियम, मुल्लांपुर में राजेश पुरी मेमोरियल इंटर-हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का 8वां एडिशन आयोजित करेगी। टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानकारी आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताई गई, जिसे जयदीप एस. चंदेल, वाइस प्रेसिडेंट, ओल्ड सनावरियन सोसाइटी; नवजोत सिंह जम्मू, जॉइंट सेक्रेटरी, ओएसएस और कैप्टन, शिवालिक हाउस; गुरनव भट्टी, ओनर, जीबी लेजेंड्स; उदयकरण खटरा, कैप्टन, हिमालय हाउस, मयंक ओबेरॉय, कैप्टन, नीलगिरी हाउस और रेवंत गुप्ता, कैप्टन, विंध्य हाउस ने संबोधित किया। इस मौके पर खास बात ये रही कि टीमों की जर्सीज भी गुरनव भट्टी, अमित सूद, सीईओ, जीबी लेजेंड्स और दुर्गेश तुकनायत (एल्यूमनस, ओएस बैच ऑफ 86) ने मिलकर लॉन्च कीं। इस मौके पर टूर्नामेंट के मैचों का ड्रॉ भी हुआ। यह टूर्नामेंट, महान मैथ टीचर स्वर्गीय राजेश पुरी की याद में शुरू किया गया था, जिन्होंने लगभग तीन दशकों तक इस संस्थान में सेवा की। यह उनकी मेंटरशिप, अनुशासन और प्रेरणा की हमेशा के लिए जीवंत रहने वाली विरासत का सम्मान करता है, जिसने सनावर में स्टूडेंट्स की कई पीढ़ियों को बनाया और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया।

इजराइल का तेहरान और बेरूत पर हमला ईरान ने जवाब में दागीं मिसाइलें

नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजराइली हमले को चुनौती दी जाएगी: आतंकी समूह

एजेंसी (हि.स.)
तेल अवीव/ तेहरान

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर नए हमले किए। इजराइल ने तेहरान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों में बमबारी की गई है। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी हैं।

फोटोः हि.स.

फॉक्स न्यूज चैनल और द यरुशलम पोस्ट अखबार के मुताबिक, इजराइल की सेना ने तेहरान में वहां की आतंकी संरचना को लक्ष्य किया। साथ ही बेरूत के दहियाह इलाके में आतंकी समूह हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला किया। हमले के दौरान दक्षिणी लेबनानी बॉर्डर पर सायरन बजाए गए। ईरान के मिसाइलें दागते ही इजराइल में भी सायरन बजाए गए। इस बीच हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप में लोगों से शुक्रवार सुबह बॉर्डर के पास के इलाकों को खाली करने की अपील की। आतंकी समूह ने कहा, लेबनान की आजादी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजराइली हमले को चुनौती दी जाएगी। इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने बहरीन की राजधानी में एक होटल और दो रिहायशी इमारतों पर हमला किया है। अधिकारियों ने बताया कि ईरानी सेना ने गुरुवार को बहरीन में एक होटल और दो रिहायशी इमारतों पर हमला किया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में मनामा में एक इमारत पर हमले की पुष्टि की। पोस्ट में कहा गया, ईरानी हमले ने मनामा में एक होटल और दो रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गृह मंत्रालय ने कहा, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। सिविल डिफेंस ने दो इमारतों में से एक के फ्लैट में लगी आग बुझा दी है।

अमेरिका-इजराइल का ईरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हमला

तेहरान/वाशिंगटन। अमेरिका-इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान से ईरान थर्रा उठा है। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के छठवें दिन ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित दुनिया के बेहिसाब खूबसूरत और प्रतिष्ठित फुटबाल मैदान 'आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' को निशाना बनाया। इस बमबारी में इसका 12 हजार सीटों की क्षमता वाला इंडोर एरिना पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ईरान इंटरनेशनल समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान सरकार ने आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर अमेरिकी-इजराइली हमले हमले की निंदा की है। ईरान ने माना है कि उस जगह पर बने 12,000 सीटों वाले इंडोर स्टेडियम को भारी नुकसान हुआ है। खेलमंत्री अहमद दोन्यामाली ने घटनास्थल का दौरा किया और हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून और ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन बताया। उन्होंने दुनिया भर से जवाबदेही तय करने की अपील की। अमेरिका और इजराइल ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तेहरान का आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईरान का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित खेल परिसर है। इस फुटबाल स्टेडियम की क्षमता लगभग 78,000 से 1,00,000 के बीच है। इंडोर एरिना का उपयोग वॉलीबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल और फुटसल के लिए किया जाता रहा है। कॉम्प्लेक्स में अन्य सुविधाएं भी हैं। इसमें एक कृत्रिम झील (रोइंग और कयाकिंग के लिए), तैराकी केंद्र, वेलोड्रोम (साइकिलिंग) और प्रशिक्षण मैदान शामिल हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। मोहम्मद रजा शाह के शासनकाल में इसका निर्माण 1974 के एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए किया गया था। इसने 1976 एएफसी एशियाई कप जैसे कई बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी की है। स्थापना के समय मूल रूप से इसे 'आर्यमेहर स्टेडियम' कहा जाता था। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इसका नाम बदलकर आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया।

स्लीपर बस पलटी-ड्राइवर की मौत, शादी में जा रहे 20 से अधिक रिश्तेदार घायल

एजेंसी (हि.स.)
अजमेर

शहर में शुक्रवार तड़के एक सड़क हादसे में शादी समारोह में जा रही स्लीपर बस पलट गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि दुल्हन पक्ष के 20 से अधिक रिश्तेदार घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार बस अहमदाबाद से सीकर जा रही थी। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे आदर्श नगर थाने के सामने हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। हादसे में घायल किरण अग्रवाल ने बताया कि सात मार्च को सीकर में उनकी बहन की बेटी की शादी है। दुल्हन पहले ही सीकर पहुंच चुकी थी, जबकि बाकी रिश्तेदार बस से वहां जा रहे थे। उन्होंने बताया कि हादसे के समय सभी यात्री सो रहे थे। अचानक जोरदार झटका लगा और बस में चीख-पुकार मच गई, तब उनकी आंख खुली।

फोटोः हि.स.

घायलों के अनुसार बस पलटते समय जोरदार धमाका भी हुआ था। हादसे के बाद कई यात्री बस में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। सीओ मनीष बड़गुजर ने बताया कि स्लीपर बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया और अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। कई घायलों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार हादसे में बस चालक विजय सिंह (55) निवासी अहमदाबाद की मौत हो गई। प्रारंभिक आशंका है कि चालक को हार्ट अटैक आया हो या फिर नींद की झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई हो। हालांकि जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चालक की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में अभिषेक अग्रवाल (33), केशवी (2), रेणु (45), बृजमोहन अग्रवाल (56), सुमित अग्रवाल (45), दिनेश प्रसाद (50), किरण (52), बृजमोहन पटेल (20), जीतू महाराज (50), मयूर चौहान (20), दिनेश अग्रवाल (54), आशा मोयल (60), जतिन (25), पायल (30), वंदना (65), खेमचंद अग्रवाल (50), इरल अग्रवाल (20), दिनेश (62), सुनीता (50), हरीश अग्रवाल (60), अंजलि (50), विपिन (50) और उत्सव (20) घायल हुए हैं।

ईडी का अनिल अंबानी और रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी कई कंपनियों पर छापा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के समूह की कंपनी 'रिलायंस पावर लिमिटेड' के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत मुंबई और हैदराबाद में कई स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी अनिल अंबानी और रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी कर रहे हैं। ईडी की 15 टीमें ने आज सुबह इस कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है।

बताया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी अनिल अंबानी की कंपनी और उसके अधिकारियों से जुड़े लगभग 10-12 ठिकानों पर दोनों शहरों में छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई के तहत मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की जा रही है। एजेंसी ने इन स्थानों में कंपनी के कार्यालय, अधिकारियों के निजी ठिकाने और अन्य संबंधित परिसर को शामिल किया है। छापेमारी के दौरान एजेंसी की टीमों ने दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य जरूरी सामग्री जब्त की है।

ईडी की यह कार्रवाई एजेंसी की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें बैंक धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं की गहन पड़ताल की जा रही है। ईडी ने पहले ही संकेत दिया था कि अनिल अंबानी से जुड़े विभिन्न समूह कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है और संदिग्ध लेन-देन की पहचान की जा रही है।

सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट क्रैश में दोनों पायलटों की मौत

एजेंसी (हि.स.)
कार्बी आंगलोंग (असम)

असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में गुरुवार देर शाम को सुखोई-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से दोनों पायलटों की मौत हो गई। दोनों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और को-पायलट लेफ्टिनेंट पुर्वेश दुरागकर के रूप में हुई है। लेफ्टिनेंट पुर्वेश आईएएफ के फ्लाइंग नेविगेटर थे। हादसे की आधिकारिक जानकारी आईएएफ ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। दुर्घटना स्थल से दोनों वायु सैन्य कर्मियों के शव मिल गए हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक्स पोस्ट में भारतीय वायु सेना ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुर्वेश दुरागकर के निधन की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि दोनों को सुखोई-30 दुर्घटना में घातक चोटें आईं। आईएएफ ने कहा है कि इस हादसे पर भारतीय वायु सेना के समस्त कर्मी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इस

फोटोः हि.स.

शोक के समय दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह हादसा गुरुवार रात लगभग 7 बजे के आसपास हुआ। विमान से संपर्क टूटने के बाद जोरहाट वायुसेना की टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। हादसास्थल पर वायु सेना की टीम को पहुंचने में लगभग चार घंटे का समय लगा। हालांकि, हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया गया है कि जोरहाट से टेक-ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के गांवों के लोगों में डर फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यह दुर्घटना कार्बी आंगलोंग जिलांतर्गत रंगखेला के चोकीहोला के नीलिप ब्लॉक के पास एक दूर पहाड़ी इलाके में हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात लगभग 7 बजे के आसपास एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जो आसपास की पहाड़ियों में गूंजी और आसपास की बस्तियों में दहशत फैल गई। चश्मदीदों ने कहा कि आवाज बहुत तेज थी और पहाड़ी इलाके में गूंजी, जिससे गांव वालों को शक हुआ कि शायद इलाके में कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिर गया है। कुछ लोगों ने धमाके के तुरंत बाद पहाड़ियों की तरफ से धुआं उठते हुए भी देखा। सूत्रों ने बताया कि एयरक्राफ्ट सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट था, जिसने शाम को जोरहाट से उड़ान भरी थी। क्रैश साइट इनसानी आबादी से दूर एक जंगली और पहाड़ी इलाके में है, जिससे वहां के लोगों के लिए तुरंत पहुंचना मुश्किल था।

संक्षिप्त-समाचार

डीजे बजाने को लेकर झड़प में एक की मौत, दो गंभीर

गिरिडीह। नगर थाना इलाके स्थित हुट्टीबाजार - दास मुहल्ले में डीजे बजाने को लेकर हिंसक विवाद हुआ। इसमें चार युवकों ने तीन सगे भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस घटना में अजय दास (30) की मौके पर ही मौत हो गई। एवं उसके दो अन्य भाई गंभीर रुप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि होली बीतने के दूसरे दिन गुरुवार की देर रात डीजे बजाने को लेकर पहले बच्चों में विवाद हुआ। इसमें दो पड़ोसी आपस में भीड़ गये। झड़प के दौरान युवकों ने तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें अजय दास की मौत हो गई। घटना में दो अन्य भाई राजेश दास, प्रद्युम्न दास गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना में रौबिन दास, रोनित दास, रोहित और रवि दास सहित एक अन्य युवक शामिल है। घटना के बाद सारे आरोपित फरार हो गए। घटना के बाद मृतक के शव को सदर अस्पताल लाया गया। जबकि सूचना मिलते ही डीएसपी नीरज सिंह और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे। डीएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजनों से घटना की जानकारी ली गई है। इस संबंध में नगर थाना प्रभारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात से ही छापेमारी की जा रही है। सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जमशेदपुर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल 17 थाना प्रभारियों का तबादला

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए एसएसपी पीयूष पांडेय ने एक साथ 17 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार देर रात अधिकारिक आदेश जारी किया गया,जिसमें कई थानों के प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार साकची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाकर सीतारामडेरा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार को स्थानांतरित कर बमार्माइंस थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। सिदगोड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार को उनके पद से हटाकर जमशेदपुर कोर्ट का सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। इसी क्रम में टेल्को थाना प्रभारी प्रशांत कुमार को उनके पद से हटाकर साकची सीसीआर में भेजा गया है। बमार्माइंस थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव को जादूगोड़ा का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। वहीं बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव को साकची थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह को हटाकर मुसाबनी का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि मुसाबनी सर्किल इंस्पेक्टर उमेश कुमार ठाकुर को बागबेड़ा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। जादूगोड़ा सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद को टेल्को थाना प्रभारी बनाया गया है। साकची सीसीआर में पदस्थ फैज अहमद को सिदगोड़ा थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा जमशेदपुर कोर्ट के सुरक्षा प्रभारी राजेंद्र मुंडा को घाटशिला का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। अजय कुमार ठाकुर को पटमदा का सर्किल इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार को उनके पद से हटाकर गोलमुरी पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया है। जादूगोड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार मंडल को भी हटाकर गोलमुरी पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं नीरज कुमार को बोड़ाम का नया थाना प्रभारी बनाया गया है,जबकि ईश्वर दयाल मुंडा को जादूगोड़ा का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को अपने-अपने नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल प्रभाव से योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

बच्चा चोरी की अफवाह पर युवक की बेरहमी से पिटाई

खूंटी। जिले में एक बार फिर बच्चा चोरी की अफवाह ने लोगों के बीच दहशत और अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। रनिया थाना क्षेत्र के सोदे गांव में गुरुवार की देर शाम ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में एक युवक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांध दिया और काफी देर तक उसके साथ मारपीट करते रहे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले आई। इस संबंध में रनिया के थाना प्रभारी श्यामल कुंभकार ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार देर शाम सोदे गांव के पास एक युवक को एक छोटे बच्चे के साथ कोयल नदी की ओर जाते देखा गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने शोर मचा दिया कि कोई व्यक्ति बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जा रहा है। देखते ही देखते गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। गुस्साई भीड़ ने युवक को बच्चे के साथ पकड़ लिया और बिना कोई पुष्टि किए उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने उसे पास के एक पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से मारपीट की। घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने भी युवक पर हाथ उठा दिया। युवक लगातार अपनी सफाई देता रहा और बच्चा चोरी के आरोप से इनकार करता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। घटना की सूचना मिलने के बाद रनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। पुलिस उसे थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई। युवक सोदे गांव का ही रहने वाला लच्छु कुमार है, जो ट्रक में खलासी का काम करता है। प्रारंभिक जांच में बच्चा चोरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

होली के जश्न में नाबालिगों को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाने वाला आरोपित गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। होली उत्सव के दौरान नाबालिग बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने के मामले में सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने बीती देर रात एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने गांव में साउंड बॉक्स लगाकर नाच-गाना करते समय तीन नाबालिग बच्चों को दबावपूर्वक शराब पिला दी थी, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 3 मार्च 2026 की रात करीब 7:30 बजे ग्राम सुकली की है। आरोपित सोनू दरवेश (34 वर्ष), निवासी इंदिरा आवास वार्ड नंबर 4 भाटापारा सुकली, अपने घर के सामने साउंड बॉक्स लगाकर होली के मौके पर नाच-गाना कर रहा था। इसी दौरान तीन नाबालिग बच्चे भी वहां डांस करने पहुंचे। आरोप है कि सोनू दरवेश ने अपने घर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब मिलाकर तीनों बच्चों को जबरन पिला दी। शराब पीने के बाद बच्चों को नशा हो गया और वे उल्टी करने लगे। परिजन उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और नाबालिग बच्चों व उनके परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की।

भोपाल में आवारा कुत्तों को लेकर फूटा रहवासियों का गुस्सा, देर रात प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जेल रोड करोंद स्थित मैपल ट्री सोसायटी में गुरुवार देर रात आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सोसायटी गेट पर एकत्र हो गए और नगर निगम तथा डॉग लवर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया।

फोटोः हि.स.

प्रदर्शन गुरुवार रात करीब 11 बजे के बाद शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। रहवासियों का कहना है कि सोसायटी में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में कुत्ते यहां आ गए हैं, जिससे काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में कुछ बुजुर्गों और बच्चों को भी कुत्तों ने काट लिया, जिससे कॉलोनी में डर का माहौल है। रहवासियों के मुताबिक उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायत करने पर कुछ डॉग लवर्स उनके खिलाफ थाने में झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने सोसायटी के गेट पर बैठकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि कई महीनों से कॉलोनी के लोग इस समस्या से परेशान हैं। आवारा कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे भयभीत हैं। रहवासियों का यह भी आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और नगर निगम डॉग लवर्स के दबाव के कारण कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से चर्चा की और समस्या के समाधान के लिए 5 दिन का समय मांगा है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे।

बलौदाबाजार के तहसील कार्यालय में लगी आग

रायपुर। बलौदाबाजार शहर के ऐतिहासिक तहसील कार्यालय में शुक्रवार करीब 5 बजे आग लगी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में लपटें तहसील परिसर के कई हिस्सों तक फैलने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग लगने से तहसीलदार कार्यालय और रिकॉर्ड रूम के कुछ हिस्से जले हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम प्रकाश कोरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग तहसील परिसर में स्थित एसडीओपी कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग की ओर से शुरू हुई। जो देखते ही देखते तहसीलदार कार्यालय की ओर फैलने लगी। जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह का समय होने की वजह से कार्यालय में ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे, लेकिन सूचना मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। रिकॉर्ड रूम पूरी तरह सुरक्षित है और सभी दस्तावेजों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया है।

बिहार में राजद ने झामुमो की राजनीति खत्म की, अब नीतीश पर टिप्पणी कर रहे : भाजपा

एजेंसी (हि.स.)
रांची

फोटोः हि.स.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि जिस पार्टी की राजनीतिक हत्या बिहार में राजद की ओर से कर दी गई, वह आखिर किस मुंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि झामुमो को बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करने से पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनकी समीक्षा बैठक का क्या हुआ।

साह ने गुरुवार देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार चुनाव में बिना लड़े हार का सामना करने के बाद झामुमो ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि चुनाव परिणाम के बाद इंडी गठबंधन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन हकीकत यह है कि समीक्षा तो दूर, आज स्थिति यह है कि हर दूसरे दिन कांग्रेस के नेता ही झामुमो को कोसते और कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि झामुमो यह बताए कि राजद कोटे के मंत्री को बाहर करने की बात कब तक पूरी होगी, या फिर बिहार चुनाव के दौरान दिए गए सारे बयान केवल जुमलेबाजी थे। साह ने आगे कहा कि बिहार में नेतृत्व और राजनीतिक फैसलों को लेकर जो भी निर्णय हुआ है, वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का सामूहिक और लोकतांत्रिक निर्णय है। बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है और उसी जनादेश के अनुरूप सभी दलों की सहमति से निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की मिसाल है, जहां नीतीश कुमार ने स्वयं और अपनी पार्टी के भीतर सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

लाल निशान पर खुला शेयर बाजार सेंसेक्स 354 अंक टूटा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। शुरूआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 353.69 अंक यानी 0.44 फीसदी टूटकर 79,662.21 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 117.70 अंक यानी 0.48 फीसदी गिरकर 24,617.75 अंक पर कारोबार कर रहा है।

शेयर बाजार में एक दिन की तेजी के बाद गिरावट दिख रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयर गिरावट के साथ खुले। इंडिगो और आईसीआईसीआई बैंक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, टाटा स्टील, मारुति, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स और भारती एयरटेल में भी गिरावट आई है। वही, बीईएल, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रिलायंस और इटरनल के शेयरों में तेजी है।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले लगातार चार दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 899.71 अंक यानी 1.14 फीसदी की तेजी के साथ 80,015.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 285.40 अंक यानी 1.17 फीसदी की बढ़त के साथ 24,765.90 पर बंद हुआ था।

रोष नैला रेलवे फाटक पर जाम के खिलाफ फूटा जनआक्रोश

ओवरब्रिज की मांग को लेकर नगर बंद और चक्काजाम

एजेंसी (हि.स.)
जांजगीर-चांपा

नैला रेलवे फाटक पर वर्षों से लगने वाले जाम और लंबे समय से लंबित रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर आज शुक्रवार को लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। क्षेत्र की जनता, व्यापारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने नगर बंद और चक्काजाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप ने किया, जिनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और आम नागरिक भी शामिल हुए।

फोटोः हि.स.

आंदोलन के तहत नैला के परशुराम चौक में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, वहीं नैला-जांजगीर रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर नगर बंद रखा गया। इस दौरान अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह, जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू सहित नैला नगर व्यापारी संघ और कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैला रेलवे फाटक पर आए दिन लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम के कारण मरीज, विद्यार्थी, व्यापारी और रोजाना यात्रा करने वाले लोग घंटों फंसे रहते हैं। कई बार एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि रेलवे फाटक की समस्या वर्षों से क्षेत्र की जनता को परेशान कर रही है। इस संबंध में कई बार रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव बजट में शामिल होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। आंदोलनकारियों ने नैला रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि जब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा चांपा के मिशन अस्पताल समपार के पास अंडरब्रिज निर्माण, नहरिया बाबा के पास फुट ओवरब्रिज निर्माण और जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग भी की जा रही है। साथ ही गोंडवाना एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस के नैला में ठहराव की मांग भी आंदोलनकारियों ने उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैला ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से बलौदा, पहरिया और पंतोरा मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से परेशान होकर अब जनता और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं।

आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस और स्कूल बसों के लिए बायपास मार्ग से आवागमन की व्यवस्था की गई। वहीं स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि जल्द ही ओवरब्रिज निर्माण और अन्य मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

खो-खो के मैदान से भारतीय महिला हॉकी टीम तक छोटे गांव की बेटी रुताजा दादासो पिसाल की उड़ान

आगामी एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप क्वालीफायर, हैदराबाद (तेलंगाना) के लिए भारतीय टीम में शामिल

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

महज 23 वर्ष की उम्र में रुताजा दादासो पिसाल भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की नियमित खिलाड़ी बन चुकी हैं। मिडफील्ड में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए पहचानी जाने वाली रुताजा को एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 क्वालीफायर, हैदराबाद (तेलंगाना) के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह टूर्नामेंट 8 से 14 मार्च तक आयोजित होगा।

महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से कस्बे फलटन से आने वाली रुताजा का हॉकी तक का सफर थोड़ा अलग रहा। उन्होंने हॉकी इंडिया के हवाले से कहा, हॉकी से पहले हम स्कूल में खो-खो खेलते थे। महाराष्ट्र में यह खेल काफी लोकप्रिय है। हमारे शिक्षकों ने देखा कि हमारी दौड़ अच्छी है और स्टैमिना भी अच्छा है, इसलिए उन्होंने हमें हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं से मेरी हॉकी की यात्रा शुरू हुई। रुताजा ने आगे कहा, मैंने करीब 12 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया। पुणे की अपनी अकादमी में प्रवेश के लिए मुझे फिटनेस और एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ा था। मैं उस टेस्ट में पास हो गई और वहीं से मेरा हॉकी करियर आगे बढ़ा। ऐसे गांव से आने वाली रुताजा के लिए यह रास्ता आसान नहीं था, जहां लड़कियों का खेलों में आगे आना आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरे गांव में लड़कियों का हॉकी खेलना बहुत सामान्य नहीं था। उस समय परिवार भी सोचते थे कि बच्चों को खेल के लिए बाहर भेजना चाहिए या नहीं। लेकिन गांव के एक कोच ने हमारा समर्थन किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद रुताजा ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया और जूनियर महिला हॉकी टीम में जगह बनाई। उन्होंने 2023 में महिला जूनियर एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा

फोटोः हि.स.

रहीं, जिसके बाद उन्हें सीनियर टीम के कैंप में मौका मिला। पिछले दो वर्षों से रुताजा सीनियर राष्ट्रीय कैंप का हिस्सा हैं और उनका मानना है कि इससे उनके खेल में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, जूनियर और सीनियर कैंप में कई समानताएं हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण की तीव्रता कहीं ज्यादा होती है। पिछले कुछ वर्षों से कैंप में रहने से मेरे खेल में काफी सुधार हुआ है। मिडफील्ड में खेलने के बावजूद सर्कल के अंदर उनकी समझ और मूवमेंट उन्हें गोल करने के मौके दिलाती है। सीनियर टीम के लिए 20 मैचों में वह अब तक सात गोल कर चुकी हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वह पहले फॉरवर्ड के रूप में भी खेल चुकी हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल मैं मिडफील्डर के रूप में खेल रही हूं, लेकिन पहले मैं फॉरवर्ड की भूमिका निभाती थी। टीम में कभी-कभी किसी एक पोजिशन पर ज्यादा खिलाड़ी होते हैं और दूसरी जगह कम, इसलिए हमें टीम की जरूरत के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है।

टीम के मौजूदा लक्ष्य के बारे में रुताजा ने कहा, इस समय हमारा मुख्य लक्ष्य एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है। इसके बाद सबसे बड़ा सपना लॉस एंजिलिस ओलंपिक में खेलना है। हम हर बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करना और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। अपनी व्यक्तिगत तैयारी पर उन्होंने कहा, मेरी ताकत गोल करना और पेनल्टी कॉर्नर बनवाना है, इसलिए मैं उसी पर काम कर रही हूं। इसके अलावा गेंद को जल्दी वापस हासिल करने और ड्रिब्लिंग की गति बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही हूं। मुझे खुद को और बेहतर बनाना है और मुश्किल परिस्थितियों में अपने साथियों का साथ देना है, ताकि टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर सके।

इंडियन वेल्स 2026: वीनस विलियम्स पहले दौर में हारकर बाहर हुई

एजेंसी (हि.स.)
इंडियन वेल्स (कैलिफोर्निया)

फोटोः हि.स.

सात बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स का बीएनपी परिबास ओपन 2026, जिसे इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, में अभियान पहले ही दौर में समाप्त हो गया। फ्रांस की डायने पैरी ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में वीनस को 3-6, 6-7 (4), 1-6 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

45 वर्षीय वीनस विलियम्स को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सिंगल्स और डबल्स ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड दिया गया था। यह उनके इंडियन वेल्स में पदार्पण के 30 साल बाद की वापसी थी। उन्होंने पहली बार 1996 में 15 वर्ष की उम्र में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। मुकाबले में पहले सेट में पिछड़ने के बाद वीनस ने दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए मुकाबला बराबरी पर ला दिया, लेकिन 23 वर्षीय डायने पैरी (विश्व रैंकिंग 111) ने तीसरे सेट में पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करते हुए आसानी से जीत दर्ज कर ली। यह वीनस विलियम्स की इस टूर्नामेंट में 10वीं उपस्थिति थी और 2024 के बाद उनकी पहली वापसी भी। 2024 में भी वह वाइल्ड कार्ड के जरिए खेलते हुए पहले ही दौर में हार गई थीं। पिछले वर्ष उन्हें वाइल्ड कार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। मैच से पहले वीनस ने कहा था, मैं इंडियन वेल्स लौटने को लेकर बहुत उत्साहित हूं और कैलिफोर्निया में खेलने के लिए घर वापसी जैसा महसूस कर रही हूं। अब डायने पैरी दूसरे दौर में अमेरिका की 15वीं वरीयता प्राप्त मैडिसन कीज से शनिवार को मुकाबला करेंगी। वीनस विलियम्स लगातार आठवां डब्ल्यूटीए सिंगल्स मुकाबला हार गई हैं। पिछले वर्ष वाशिंगटन में वापसी के दौरान उन्होंने एकमात्र जीत दर्ज की थी। जनवरी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में हिस्सा लिया था, जहां वह सिंगल्स और डबल्स दोनों में पहले दौर में हार गई थीं। उस समय वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनी थीं, उन्होंने जापान की किमिको दाते का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 2015 में 44 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। वीनस ने हाल ही में टेक्सास के ऑस्टिन में आयोजित एटीएक्स ओपन में भी वाइल्ड कार्ड के जरिए भाग लिया था, जहां वह पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की अजला टोमल्यानोविच से हार गई थीं।

सैमसन टी20 विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की दौड़ में

एजेंसी (हि.स.)
दुबई

फोटोः हि.स.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम उन आठ खिलाड़ियों में शामिल किया है जिन्हें टी20 विश्व कप के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए नामित किया गया है। जिन अन्य खिलाड़ियों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है उनमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी और कप्तान एडन मार्क्रम, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र और बल्लेबाज टिम सीफर्ट और अमेरिकी गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक शामिल हैं।

सैमसन को टूर्नामेंट के शुरूआती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन पिछले दो मैच में उन्होंने नाबाद 97 और 89 रन की पारी खेल कर भारत को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में अब तक चार मैच में 77.33 के औसत और 201.73 के स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए हैं। जैक्स ने टी20 विश्व कप में अपनी टीम को आठ में से छह मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें चार बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। उन्होंने आठ मैचों में 226 रन बनाए और नौ विकेट लिए हैं। फरहान ने छह पारियों में 383 रन बनाकर टी20 विश्व कप के किसी एक टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ शतक बनाए। किसी एक टी20 विश्व कप में यह कारनामा करने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं।

ईटीपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदेंगे द्रविड़ और अश्विन

लंदन। दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और रविचंद्रन अश्विन उस भारतीय समूह का हिस्सा हैं जो यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में एक फ्रेंचाइजी खरीदने जा रहा है। बीबीसी स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में होने वाले छह टीमों के टूर्नामेंट में ग्लासगो स्थित फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए इस समूह ने एक समझौते पर सहमति जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईटीपीएल नीदरलैंड के रॉटरडैम स्थित अपनी फ्रेंचाइजी को भी दक्षिण अफ्रीका के निवेशकों के एक समूह को बेचने की तैयारी में है। इस समूह में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी, हेनरिक क्लासेन और जोंटी रोड्स भी शामिल हैं। संभावना है कि इस महीने के आखिर में एक कार्यक्रम में दोनों फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एम्स्टर्डम, बेलफास्ट और एडिनबर्ग में स्थित ईटीपीएल फ्रेंचाइजी को जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवेशकों को बेच दिया गया था। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि अश्विन ईटीपीएल में खेलेंगे या नहीं। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया था। अब वह वैश्विक फ्रेंचाइजी लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, अश्विन की भागीदारी बेहद दिलचस्प है।

फीफा विश्व कप 2026 से पहले मोरक्को के कोच वालिद रेग्रागुई ने दिया इस्तीफा

एजेंसी (हि.स.)
रबात

मोरक्को की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच वालिद रेग्रागुई ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने फीफा विश्व कप 2026 से कुछ महीने पहले लिया है। पिछले कई हफ्तों से उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। रेग्रागुई ने अपने इस्तीफे का कारण थकान बताया है। 50 वर्षीय रेग्रागुई ने 2022 में फीफा विश्व कप 2022 में मोरक्को को ऐतिहासिक सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। यह किसी भी अफ्रीकी देश का विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

इसके अलावा इसी साल जनवरी में उन्होंने टीम को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल तक भी पहुंचाया था, जहां मोरक्को को सेनेगल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मीडिया

फोटोः हि.स.

रिपोर्ट्स के अनुसार अब मोरक्को टीम की कमान मोहम्मद औहबी संभाल सकते हैं। उन्होंने पिछले साल चिली में आयोजित अंडर-20 विश्व कप में मोरक्को की टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सितंबर 2022 में कोच बनने के बाद रेग्रागुई का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा। उनके कार्यकाल में मोरक्को ने 49 मैचों में 36 जीत दर्ज की, 8 मुकाबले ड्रॉ रहे और सिर्फ 5 में हार मिली। इसी दौरान टीम ने जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच लगातार 19 जीत दर्ज कर राष्ट्रीय टीमों के बीच लगातार सबसे अधिक जीत का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। बताया जा रहा है कि जनवरी में नेशंस कप के विवादित फाइनल में हार के बाद ही रेग्रागुई इस्तीफा देना चाहते थे। लगभग चार साल तक टीम की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थक चुके थे। हालांकि मोरक्को फुटबॉल संघ ने उनसे नए कोच के चयन तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया था।

मोरक्को की टीम इस महीने दो अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच खेलेगी। टीम 27 मार्च को मैड्रिड में इक्वाडोर से भिड़ेगी, जबकि चार दिन बाद फ्रांस के लेंस में पैराग्वे के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। आगामी फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को को ग्रुप-उ में ब्राजील, स्कॉटलैंड और हैती के साथ रखा गया है। मोरक्को के कप्तान अशरफ हकीमी ने सोशल मीडिया पर रेग्रागुई को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता, जुनून और विजन ने खिलाड़ियों के साथ-साथ पूरे देश और दुनिया भर के प्रशंसकों को प्रेरित किया।

लियोनेल मेस्सी ने डोनाल्ड ट्रंप को रत्न जड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

फोटोः हि.स.

दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने पिछले साल मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) कप जीतने पर इंटर मियामी को सम्मानित करने के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रत्नजड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की। इंटर मियामी ने दिसंबर में वैंकूवर व्हाइटकैप्स को हराकर मेजर लीग सॉकर का खिताब जीता था। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेस्सी को लगातार दूसरे सत्र में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) चुना गया था।

ट्रंप ने कहा, लियो (मेस्सी) आप टीम से जुड़े और आपकी टीम ने जीत हासिल की। आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं था। सच कहूं तो आप पर जितना दबाव था, उतना किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि आप जीत दिलाने में सफल रहेंगे और आपने ऐसा किया। मेस्सी ने ट्रंप के साथ समारोह में प्रवेश किया। वर्ष 2023 में मियामी से जुड़ने वाले मेस्सी ने कार्यक्रम के दौरान भाषण नहीं दिया।

ट्रंप ने मेस्सी को संबोधित करते हुए कहा, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते थे। आप दुनिया की कोई भी टीम चुन सकते थे, लेकिन आपने मियामी को चुना। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हम सभी को इस सफर में शामिल किया। आप प्रतिभाशाली और एक बेहतरीन इंसान हैं।

मनोरंजन दर्पण

ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा निभाएंगी खास भूमिका

प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह ऑस्कर पुरस्कार 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रियंका का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि वह इस बार हॉलीवुड के दिग्गज सितारों रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऐनी हैथवे के साथ मंच शेयर करती नजर आएंगी। अकादमी द्वारा जारी सूची के अनुसार, प्रियंका इस साल ऑस्कर समारोह में प्रेजेंटर के रूप में पुरस्कार प्रदान करेंगी। ग्लोबल स्टार बन चुकीं प्रियंका की इस उपलब्धि से भारतीय प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

10 साल बाद ऑस्कर मंच पर वापसी

गौरतलब है कि प्रेजेंटर के रूप में यह प्रियंका की ऑस्कर मंच पर वापसी होगी। इससे पहले वह 2016 में आयोजित अकादमी पुरस्कार समारोह में भी एक अवॉर्ड प्रस्तुत कर चुकी हैं। उस समय भी उनकी मौजूदगी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय कलाकारों की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाल ही में वह गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में भी प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुकी हैं।

भारत में कब और कहां देखें समारोह

दुनिया के 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजिल्स के प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर में किया जाएगा। अमेरिका में यह समारोह 15 मार्च को आयोजित होगा, जबकि भारत में इसका सीधा प्रसारण 16 मार्च 2026 को सुबह 5:30 बजे से देखा जा सकेगा। भारतीय दर्शक इसे जियो हॉटस्टार और स्टार नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे। वहीं अमेरिका में इसका प्रसारण एबीकी और हुलू पर किया जाएगा।

अदा शर्मा ने 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर तोड़ी चुप्पी

निमार्ता विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' इन दिनों सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। साल 2023 में रिलीज हुई 'द केरल स्टोरी' की सफलता के बाद इसका दूसरा भाग दर्शकों के बीच लाया गया है। हालांकि, फिल्म में पहली किस्त की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा की अनुपस्थिति ने प्रशंसकों को चौंका दिया। अब अभिनेत्री ने सीक्वल में नजर न आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

'जिस फिल्म में नहीं होती, उस पर बोलना सही नहीं'

एक कार्यक्रम के दौरान अदा शर्मा ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें उन फिल्मों के बारे में बात करना पसंद है, जिनमें वह काम करती हैं। उन्होंने कहा, ‟जब मैं किसी फिल्म का हिस्सा नहीं होती, तो मुझे लगता है कि सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए उसके बारे में बोलना सही नहीं है।‟ अभिनेत्री ने आगे कहा कि उन्हें सीक्वल का प्रस्ताव मिला या नहीं, यह फिल्म निमार्ताओं और कलाकार के बीच की निजी बात है और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए।

बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर भी दिया जवाब

फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर अदा ने कहा कि दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सबसे अहम है। उन्होंने कहा, ‟मेरे दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर फिल्म में देखना चाहते हैं। मेरी पहली फिल्म '1920' से लेकर 'द केरल स्टोरी' तक मुझे अलग-अलग किरदार निभाने का मौका मिला है।

कमाई के मामले में पिछड़ी सीक्वल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' ने रिलीज के पहले सप्ताह में करीब 22.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं पहली फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने अपने पहले सप्ताह में 81.14 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। ऐसे में कमाई के मामले में सीक्वल पहली किस्त से काफी पीछे नजर आ रही है।

'हैलो बच्चों': अलख पांडे की जर्नी को सादगी से दिखाती ईमानदार कहानी

'हैलो बच्चों' ऐसी वेब सीरीज है, जिसे देखकर सबसे पहले यही महसूस होता है कि यह किसी बनावटी ड्रामा की तरह नहीं बनाई गई है। इसमें न तो जबरदस्ती का इमोशनल ओवरलोड है और न ही तेज-तर्रार ट्विस्ट का दिखावा। कहानी बहुत सरल तरीके से एक 12वीं पास शिक्षक की जर्नी दिखाती है। उसके पास साधन भले कम हों, लेकिन वह यह ठान लेता है कि पढ़ाई हर उस बच्चे तक पहुंचे, जिसे सच में इसकी जरूरत है। यही ईमानदारी इस सीरीज को खास बनाती है। ळश्ऋ ऑडियंस की पसंद को अच्छी तरह समझता है। डायलॉग से लेकर कास्टिंग तक, इस सीरीज के माहौल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। जहां कोटा फैक्ट्री छात्रों के इमोशनल बर्नआउट को दिखाती थी, वहीं ये सीरीज उस कहानी का दूसरा पहलू खोलती है- ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया को और ज्यादा विस्तार से सामने लाती है।

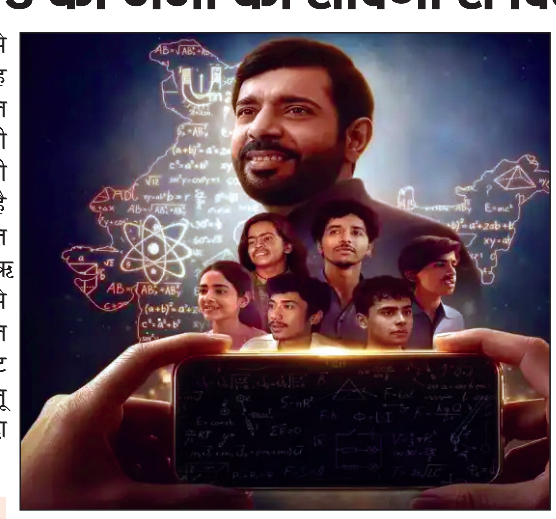

कहानी

सीरीज की शुरूआत बहुत साधारण तरीके से होती है। एक टीचर है जो कम फीस में पढ़ाना चाहता है, ताकि पैसों की वजह से कोई बच्चा पीछे न रह जाए। कोचिंग चलाते समय उसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें शिक्षा से ज्यादा फायदा दिखता है। लेकिन वह अपने फैसले पर टिका रहता है। वह मानता है कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और हर बच्चे के लिए आसान होनी चाहिए। जब वह ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करता है तो मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। कैमरा, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और पैसों की कमी। कई टीचर्स बीच में नौकरी छोड़ देते हैं। हर दिन एक नई परेशानी खड़ी रहती है। फिर भी वह हार नहीं मानता। धीरे-धीरे उसके वीडियो उन बच्चों तक पहुंचने लगते हैं जिनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। यही हिस्सा सीरीज को गर्माहट देता है। सीरीज में पांच छात्रों की अपनी-अपनी कहानियां भी चलती रहती हैं। कोई फीस नहीं भर पा रहा। कोई घर के बोझ में दबा है। कोई गलती से गलत संगत में पहुंच गया है। कोई दबाव में अपने सपनों से दूर होता जा रहा है। इन बच्चों की मुश्किलें बहुत असल लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि यह वही बच्चे हैं जो हर जगह देखने को मिलते हैं।

एक्टिंग

विनीत कुमार सिंह इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण हैं। वह टीचर के किरदार में बेहद नेचुरल लगते हैं। उनका बोलने का तरीका, पढ़ाते समय का व्यवहार और चेहरे पर हल्की थकान सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। उन्हें देखते समय ऐसा महसूस होता है कि कैमरा किसी असली शिक्षक की जिंदगी रिकॉर्ड कर रहा हो। छात्र बने कलाकार भी ईमानदारी से अभिनय करते हैं और उनकी इमोशंस साफ दिखाई देती हैं।

निर्देशन

प्रतिश मेहता का निर्देशन भी कहानी की तरह सरल है। लोकेशन छोटे कमरे और तंग गलियारे हैं। रोशनी भी बहुत हल्की रखी गई है ताकि माहौल असली लगे। ऑनलाइन पढ़ाई की परेशानियों को भी बिना किसी अतिरिक्त ड्रामा के दिखाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक कम है ताकि सीन अपने आप असर छोड़ सकें।

चंडीगढ़ प्रशासन ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य नियामकीय निगरानी को मजबूत करना, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना तथा सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना है। नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लाइसेंसिंग इकाइयों का आरक्षित मूल्यः शहर में कुल 97 खुदरा शराब विक्रय वेंड संचालित होंगे। आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के लिए लाइसेंसिंग इकाइयों का कुल आरक्षित मूल्य 454.35 करोड़ निर्धारित किया गया है।
2. ईडीपी में मामूली वृद्धिः कंट्री लिकर, , भारतीय बीयर और भारतीय वाइन के लिए एक्स-डिस्टिलरी प्राइस में अधिकतम 2% तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। यह वृद्धि आयातित वाइन, आयातित बीयर और आयातित विदेशी शराब पर लागू नहीं होगी। EDP/EBP में किसी भी वृद्धि पर विचार आबकारी नीति वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा।
3. व्यापार सुगमता - बॉन्डेड वेयरहाउसः L-1F और L-1DF लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कस्टम स्वीकृत बॉन्डेड वेयरहाउस का यू.टी. चंडीगढ़ में होना अनिवार्य नहीं रहेगा। अब ऐसे वेयरहाउस भारत में कहीं भी स्थित हो सकते हैं तथा एक वर्ष के पूर्व अनुभव की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
4. बॉन्डेड वेयरहाउस का पंजीकरणः सभी कस्टम स्वीकृत बॉन्डेड वेयरहाउस को एक्साइज पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा तथा आयात-निर्यात खेप का मासिक विवरण प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
5. रिटेल कोटा में कोई परिवर्तन नहींः कंट्री लिकर, IMFL और IFL का रिटेल कोटा यथावत रखा गया है, जिससे वर्ष 2025-26 की नीति की तुलना में राजस्व-तटस्थ स्थिति बनी रहेगी।
6. छ-10इ लाइसेंस का पुनःप्रवर्तनः संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर्स के माध्यम से शराब की बिक्री की अनुमति देने हेतु L-10B लाइसेंस को पुनः लागू किया जाएगा, जिससे विशेषकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी।

7. परिवार की परिभाषाः नीति में परिवार की स्पष्ट परिभाषा शामिल की गई है ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता और संभावित विवाद से बचा जा सके।
8. सिक्योरिटी राशि में संशोधनः रिटेल वेंड लाइसेंसधारियों के लिए सिक्योरिटी राशि को बोली राशि के 17% तक बढ़ाया गया है।
9. लाइसेंस शुल्क का भुगतानः रिटेल शराब वेंड को लाइसेंस शुल्क एवं लागू ब्याज का भुगतान अगले माह की 15 तारीख तक एकमुश्त करना होगा, जबकि पहले इसे दो किश्तों में जमा किया जाता था।
10. भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाईः निर्धारित शुल्क जमा न करने पर संबंधित L-2/L-14A लाइसेंस तथा लाइसेंसधारी के अन्य सभी लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, और कानून के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
11. बार लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदः बार लाइसेंसधारी शराब की खरीद निकटतम दो रिटेल वेंड (L-2/L-14A) से करेंगे। यदि दोनों वेंड एक ही संस्था के हों, तो तीसरे निकटतम वेंड से खरीद की जा सकेगी।
12. सीसीटीवी निगरानीः रिटेल वेंड के अतिरिक्त गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा तथा विभाग को लाइव फीड एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा।
13. कड़े अनुपालन प्रावधानः लाइसेंसधारियों द्वारा शराब के विज्ञापन संबंधी नियमों को और कड़ा किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी और सुदृढ़ की गई है।
14. बॉटलिंग प्लांट संचालनः बॉटलिंग प्लांट के कार्य दिवस पांच से बढ़ाकर छह (सोमवार से शनिवार) कर दिए गए हैं तथा राजपत्रित अवकाश पर ओवरटाइम कार्य की भी अनुमति होगी।
15. सुरक्षा व्यवस्थाः बॉटलिंग प्लांट और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनका वेतन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
16. काउ सेसः काउ सेस पूर्ववत दरों पर जारी रहेगा– 750 मि.ली. कंट्री लिकर की प्रति बोतल 0.50, 650 मि.ली. बीयर की प्रति बोतल 0.50 और 750/700 मि.ली. व्हिस्की की प्रति बोतल 1।
17. परिवहन वाहनों में GPS ट्रैकिंगः शराब के आयात, निर्यात अथवा स्थानीय आपूर्ति में प्रयुक्त सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
18. सरकारी परिसरों में रिटेल वेंडः यदि रिटेल वेंड सरकारी या प्रशासनिक परिसरों में संचालित होते हैं, तो लाइसेंसधारी को संबंधित विभाग को सीधे किराया अदा करना होगा।
19. बीयर का न्यूनतम खुदरा मूल्यः बीयर के न्यूनतम खुदरा विक्रय मूल्य को संशोधित कर एइढ के आधार पर श्रेणी-वार निर्धारित किया जाएगा।

इन उपायों का उद्देश्य नियमन को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, व्यापार को सुगम बनाना तथा यू.टी. प्रशासन के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना है, साथ ही उपभोक्ता सुविधा को बनाए रखना भी है।

कंधे की सर्जरी में हुई प्रगति पर कांफ्रेंस का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

इंडियन ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी एसोसिएशन) शोल्डर कॉन्क्लेव 2026, कंधे की सर्जरी में हुई तरक्की पर फोकस करने वाला एक नेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है। इसका उद्घाटन आज खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में हुआ और यह 7 मार्च तक चलेगा। यह आर्थोप्लास्टी सोसाइटी ऑफ ट्राइसिटी के तहत होगा। उद्घाटन समारोह में PGIMER चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) विवेक लाल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने मॉडर्न ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में लगातार एकेडमिक एक्सचेंज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कंधे की सर्जरी के जाने-माने एक्सपर्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की तारीफ की। कॉन्फ्रेंस की थीम, शोल्डर सर्जरी में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आर्थोस्कोपिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्नीक में हाल की तरक्की पर फोकस करती है जो कंधे की मुश्किल बीमारियों के मैनेजमेंट को बदल रही हैं। कॉन्क्लेव का मकसद एक्सपर्ट्स और युवा सर्जनों को कंधे की सर्जरी में नई टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नीक और क्लिनिकल नतीजों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। इस इवेंट में 180 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें देश भर के ऑर्थोपेडिक सर्जन और पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी के तौर पर भारत के कोने-कोने से जाने-माने आर्थोप्लास्टी और आर्थोस्कोपी सर्जन शामिल हैं, जो कंधे की सर्जरी में अपनी एक्सपर्टीज और लेटेस्ट इनोवेशन शेयर कर रहे हैं।

कॉन्क्लेव की एक बड़ी खासियत हैंड्स-ऑन सॉ बोन मॉडल वर्कशॉप है, जहाँ पार्टिसिपेंट्स को शोल्डर रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर और बाइसेप्स टेनोडेसिस जैसे एडवांस्ड प्रोसीजर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे मॉडर्न सर्जिकल टेक्नीक का कीमती प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। यह इवेंट ढक्क्षटएफ चंडीगढ़ के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड, प्रोफेसर विजय जी. गोनी की अच्छी लीडरशिप में ऑर्गनाइज किया जा रहा है, जो ऑर्गनाइज़िंग टीम के चेयरमैन हैं। ऑर्गनाइज़िंग टीम में प्रोफेसर समीर अग्रवाल (को-चेयरमैन), डॉ. आरती एस. दीवान (सेक्रेटरी), डॉ. दीपक कुमार (को-सेक्रेटरी), और प्रोफेसर पेबम सुदेश (ट्रेजरर) शामिल हैं। इंडियन ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी एसोसिएशन एक सब-स्पेशियलिटी एकेडमिक ऑर्गनाइजेशन है जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अंडर काम करता है। यह साइंटिफिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और एकेडमिक पहल के जरिए ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी में ज्ञान और क्लिनिकल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है - रूमेटोलॉजिक और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में शामिल ऑर्थोपेडिक सर्जनों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रेरणा पुरी में स्पोर्ट्स कांपलेक्स सेक्टर 7 का दौरा किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सुश्री प्रेरणा पुरी, आईएएस, खेल सचिव, यू.टी. चंडीगढ़ ने श्री सौरभ कुमार अरोड़ा, पीसीएस, निदेशक खेल, श्री सी.बी. ओझा, मुख्य अभियंता, तथा इंजीनियरिंग विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ के अन्य अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-7 और लेक स्विमिंग पूल का दौरा कर वहां चल रहे नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्यों की समीक्षा की। इन कार्यों का उद्देश्य खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा खिलाड़ियों और आम नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

दौरे के दौरान लेक स्विमिंग पूल में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का विस्तार से निरीक्षण किया गया। टीम ने विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य निर्धारित मानकों और समयसीमा के अनुसार किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने स्विमिंग पूल के ढांचे और उससे जुड़ी सुविधाओं के उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

इसके अलावा लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस कोर्ट और स्क्वैश कोर्ट का भी निरीक्षण किया गया। इन सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की समीक्षा करते हुए खेल सतहों की गुणवत्ता सुधारने, अवसंरचना को मजबूत करने तथा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। खेल सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नवीनीकरण और उन्नयन कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूर्ण किए जाएं। यह दौरा चंडीगढ़ प्रशासन के उस निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा खिलाड़ियों और आम जनता के लिए आधुनिक और सुलभ खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर खेलों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के लिए दो दिवसीय संवेदनशीलता कार्यशाला आरंभ

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेक्टर-26, चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों एवं अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए दो दिवसीय संवेदनशीलता कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अवसर पर श्री पुष्पेंद्र कुमार, आईपीएस, महानिरीक्षक पुलिस, चंडीगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सुश्री के. एम. प्रियंका, आईपीएस, एसपी, चंडीगढ़ पुलिस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यशाला में पुलिस विभाग, न्यायपालिका, बाल कल्याण एवं संरक्षण से जुड़े निकायों, विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रमुख हितधारकों सहित लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने समूह चर्चा एवं रैपिड-फायर सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

स्वागत संबोधन देते हुए सुश्री शिप्रा बंसल, अध्यक्ष, चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों और हितधारकों का स्वागत किया।

उन्होंने माननीय प्रशासक, यूटी चंडीगढ़, श्री गुलाब चंद कटारिया का शहर में बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, श्री मंजीत, आईपीएस, एसपी, तथा एसपी से डीएसपी स्तर तक सभी समन्वयक नोडल अधिकारियों का भी कार्यशाला के आयोजन में सक्रिय सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बाल-अनुकूल न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों और हितधारकों का निरंतर संवेदनशीलता प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह दो दिवसीय कार्यशाला जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

तकनीकी सत्रों के दौरान डॉ. के. पी. सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया।

ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इन न्यू मिलेनियम नाईपर -मोहाली के पांचवें सम्मलेन का उदघाटन

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

नाईपर, मोहाली में दिनांक 06.03.2026 को ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इन न्यू मिलेनियम के पाँचवें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन (6 से 8 मार्च, 2026) नेक्स्ट-जनरेशन थेरैप्यूटिक्स विषय पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. एस. एस. शर्मा ने अपने स्वागत संबोधन में सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं तथा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने नाईपर, मोहाली द्वारा आयोजित ऊ्रटट सम्मेलनों के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दी। नाईपर के डीन प्रो. कुलभूषण टिक्कू ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) एक प्रमुख विषय बन गया है, लेकिन पशु-अध्ययनों का कोई विकल्प नहीं है। नाईपर, मोहाली के निदेशक प्रो. दुलाल पांडा ने अपने संबोधन

में कहा कि अक एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। फामाकोइन्फॉर्मेटिक्स को खोज संबंधी विज्ञानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्रॉस-डिसिप्लिनरी शिक्षा का अत्यंत महत्व है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रो. वाई. के. गुप्ता, अध्यक्ष, अक्क्रटर कल्याणी ने अपने संबोधन में कहा कि दवा विकास की प्रक्रिया अब ह्यसेरेंडिपिटीह्ल से आगे बढ़ चुकी है और अब लक्ष्य-आधारित खोज (टारगेट-बेस्ड डिस्कवरी) पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दवा विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा कि अक नौकरियों को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि केवल नौकरियों के स्वरूप में परिवर्तन करेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रो. अनिल गुलाटी, चेयरमैन एवं सीईओ, फार्माज इंक., यूएसए ने अपने संबोधन में कहा कि नाईपर जैसे संस्थान में करियर निर्माण वास्तव में देश के निर्माण में योगदान है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. आशुतोष कुमार, सहायक प्रोफेसर, फामाकोलॉजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। देशभर से लगभग 200 फार्मास्युटिकल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, पीएचडी शोधार्थियों तथा शोधकताओं के साथ-साथ उद्योग और अकादमिक जगत के अग्रणी विशेषज्ञ एकत्रित हो रहे हैं, जो आधुनिक औषधि खोज एवं विकास के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम और अत्याधुनिक प्रगतियों पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन के वैज्ञानिक सत्रों में आधुनिक औषधि अनुसंधान के उभरते क्षेत्रों जैसे उफ्रढफ-उं२९ जीनोम एडिटिंग, उअफ्ळ सेल एवं एंटीबॉडी आधारित उपचार, ऑर्गेनॉइड मॉडल, माइटोकॉन्ड्रियल-टारगेटेड (मिटो) थेरेपी, तथा जीन थेरेपी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ-साथ अगली पीढ़ी की उपचार रणनीतियों, औद्योगिक सफलता की कहानियों, नए फामाकोलॉजिकल टार्गेट्स, उन्नत प्रयोगात्मक मॉडलों तथा औषधि खोज प्रक्रिया को तेज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क फामाकोलॉजी की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा।

समाधान शिविर में आकर करवाएं अपनी समस्याओं का समाधानः उपायुक्त

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में जिला के लोगों की समस्याओं का सभी अधिकारी टीम के रूप में कार्य कर जल्द से जल्द समाधान कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस के दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उन्होने बताया कि समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं की मुख्यमंत्री स्वयं मानिटरिंग करते हैं और समाधान शिविर से जुडते भी हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को गंभीरता से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याएं रखकर उनका जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की । उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याएं रखकर उनका जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की । उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई जिलावासियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर व तय समय सीमा में समाधान करें।

दावा

विधायक कुलवंत सिंह ने खिलाड़ियों और खेल प्रबंधकों का हौसला बढ़ाया

मान की सरकार खेल जगत का स्तर ऊपर उठाने के लिए उठा रही है बड़े कदम: कुलवंत सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

मोहाली विधानसभा क्षेत्र में हो रहे खेल टूनार्मेंटों की कड़ी के तहत- बाबा अस्ताली जी और अमर शहीद जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी स्पोर्ट्स क्लब (रजिस्टर्ड) गांव गोबिंदगढ़ की तरफ से तीसरा कबड्डी महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कबड्डी खिलाड़ियों ने अपना खेल कौशल दिखाया। इस कबड्डी कप को देखने के लिए पूरे पंजाब से बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे । तीसरे कबड्डी महाकुंभ के दौरान मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खास तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक कुलवंत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार पूरे पंजाब में खेल जगत के लिए बड़े कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो और उन्हें खेलों के लिए जरूरी और सही माहौल दिया जा रहा है। मोहाली हलके समेत पूरे पंजाब में बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिससे पंजाब के नौजवान लड़के-लड़कियां खेल के मैदान में अपना समय बिताकर अपना, अपने परिवार, पंजाब और देश का नाम रोशन कर सकेंगे।

कुलवंत सिंह ने गोबिंदगढ़ गांव में हो रहे इस तीसरे कबड्डी महाकुंभ के ऑर्गनाइजर मीत गुज्जर, रवि बाजवा, अमन बाजवा और दूसरों को बधाई दी और कहा कि ये ऑर्गनाइजर हर बार इस महाकुंभ को अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज करते हैं, जिससे इलाके के खेल प्रेमियों और स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजर का हौसला और बढ़ता है, और सभी बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स टूनार्मेंट ऑर्गनाइज करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके का डेवलपमेंट बड़े लेवल पर हो रहा है और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि हमारा पूरा इलाका तरक्की करता रहे और यहां के रहने वाले हमेशा अपने परिवार के साथ बैठकर बच्चों को खेलों और पढ़ाई की तरफ मोटिवेट कर सकें। इस मौके पर विधायक कुलवंत सिंह ने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उनके साथ हैं और ऑगेर्नाइजर हर साल बड़े टूनार्मेंट ऑर्गनाइज करते रहेंगे और प्लेयर्स को बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे। मैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को फिर से बधाई देता हूं, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं हर मौके पर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मौजूद रहूंगा। इस मौके पर पीर बाबा अस्ताली जी और अमर शहीद जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी स्पोर्ट्स क्लब (रजिस्टर्ड) गांव गोबिंदगढ़ के प्रेसिडेंट- मीत गुज्जर, वाइस प्रेसिडेंट- रवि बाजवा, अमन बाजवा, राजू गुज्जर, गुरकीरत सिंह, रविंदर सिंह, जसविंदर सिंह जैली, गोविंदगढ़ कर्मपुरी- सरपंच के अलावा कुलदीप सिंह समाना, अवतार सिंह मौली बैदवान, अकविंदर सिंह गोसल, जसपाल सिंह मटौर, डॉ. कुलदीप सिंह, गुरजंट सिंह सरपंच, जसविंदर सिंह जैली गोबिंदगढ़, जगजीत सिंह जग्गी गोबिंदगढ़, गुरप्रीत सिंह-बरियाली, परविंदर सिंह मटरां, तरलोचन सिंह मटौर, भूपिंदर सिंह पंच, के साथ-साथ इलाके के बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी मौजूद थे।

संक्षिप्त-समाचार

समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहमः पुरी

चंडीगढ़। सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावाः एक करुणामय, समावेशी और सतत समाज का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सेक्टर 20-डी, चंडीगढ़ में कद्धअउ एवं वल्क्ष सेल द्वारा किया गया। यह संगोष्ठी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें 85 से अधिक शिक्षाविदों, प्रशासकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती प्रेरणा पुरी, आईएएस, शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने समाज निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और उन्हें धैर्य व समर्पण के साथ मार्गदर्शन देना चाहिए। संत और बिच्छू की कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक को हर परिस्थिति में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। उन्होंने संगोष्ठी के विषय की सराहना करते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों के समग्र विकास पर निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रो. रवि इंदर सिंह, डीन, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, पंजाब विश्वविद्यालय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रामकृष्ण मिशन आश्रम, चंडीगढ़ के सचिव स्वामी भीतिहरणानंदजी महाराज ने मुख्य वक्तव्य देते हुए मूल्य-आधारित शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन प्रो. शंकर सहगल, समन्वयक, वल्क्ष सेल, पंजाब विश्वविद्यालय के समापन संबोधन के साथ हुआ। डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, डीन, कॉलेज द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह संगोष्ठी डॉ. सपना नंदा, प्राचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

चंडीगढ़ में CH01-DD-0001 पंजीकरण नंबर ने 53,88,000/- में बिका

चंडीगढ़। पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, यू.टी., चंडीगढ़ के कार्यालय द्वारा नई सीरीज CH01-DD के वाहन पंजीकरण नंबरों (फैंसी एवं चॉइस) की ई-नीलामी 04.03.2026 से 06.03.2026 तक आयोजित की गई। इस नीलामी में वाहन नंबर 0001 से 9999 तक के नंबरों के साथ-साथ पिछली सीरीज के बचे हुए फैंसी/विशेष पंजीकरण नंबर भी शामिल किए गए। इस प्रक्रिया में कुल 591 पंजीकरण नंबरों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जिससे ₹4,48,87,000/- का उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ, आरएलए नीलामी के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक बोली। नीलामी के दौरान CH01-DD-0001 पंजीकरण नंबर ने ₹53,88,000/- की सर्वाधिक बोली प्राप्त की, जबकि CH01-DD-0003 पंजीकरण नंबर ₹32,32,000/- की बोली के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

रिश्वतखोरी मामले में उप निरीक्षक सहित तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

गुरुग्राम। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, होमगार्ड इरफान तथा आबिद हुसैन (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आज दिनांक 06.03.2026 को माननीय न्यायालय श्रीमती रेणू राणा, एएसजे, नूंह की अदालत में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया है। यह चालान धारा 7, 7ए, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 308(2) बीएनएस के अंतर्गत दाखिल किया गया है। मामले के अनुसार, आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार तथा होमगार्ड आबिद हुसैन, थाना साइबर नूंह में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पति के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के दो मामलों की जांच में धाराएं कम करने तथा चालान शीघ्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। जांच के दौरान सतर्कता ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए होमगार्ड इरफान और आबिद हुसैन को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपियों उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, होमगार्ड इरफान तथा आबिद हुसैन (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं तथा धारा 308(2) बीएनएस के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था।

तरणजीत सिंह संधू की दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति दिल्ली की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगी : हरमीत सिंह कालका

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने श्री तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। सरदार हरमीत सिंह कालका ने कहा कि श्री तरणजीत सिंह संधू के पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व तथा देश सेवा की मजबूत भावना है, जो दिल्ली के शासन-प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तरणजीत सिंह संधू के नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली के विकास तथा जनहितकारी नीतियों को नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्री संधू की दूरदर्शी सोच और व्यापक अनुभव दिल्ली को प्रगति की नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे तथा शहर के विकास को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। सरदार हरमीत सिंह कालका ने श्री तरणजीत सिंह संधू के सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल के लिए दिल से शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे अपनी योग्यता और दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली के प्रशासन को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।